



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2018/फाल्गुन 16, 1939

No. 78]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2018/PHALGUNA 16, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्लेइंग कार्ड्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 14/43/2016-डीजीएडी.—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित उसकी सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली (जिसे आगे यहां नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स पार्कसन्स ग्राफिक्स प्रा. लि., मैसर्स पार्कसन्स कर्टासुंडी प्रा. लि. और मैसर्स टीएम प्रिंटर्स प्रा. लि. (जिसे आगे यहां "याचिकाकर्ता" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन जन गण (जिसे यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **प्लेइंग कार्ड्स** (जिसे आगे यहां "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने के लिए अधिनियम एवं पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए जांच शुरू किए जाने का अनुरोध किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 मार्च, 2017 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच किए जाने का अनुरोध किया गया है ताकि तथाकथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

क. प्रक्रिया

3. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उपनियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में स्थित चीन जन गण के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की एक प्रति भारत में चीन जन गण के दूतावास, संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार संबंधित देशों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को भेजी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत की अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अनुरोध किया।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में चीन जन गण के दूतावास को, संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबंधित सामानों के ज्ञात आयातकों को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, अगोपनीय रूपांतरण की प्रति भेजी। आवेदन की एक प्रति, जहां भी अनुरोध किया गया था, वहां अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी दी गई थी।
- घ. भारत में स्थित चीन जन गण के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के उत्पादकों/आयातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर दायर करने की सलाह दें।
- ङ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबंधित देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

चीन जन गण

1. वेंगझोऊ टियांगे प्रिंटिंग कं. लि.
 2. शेनझेन वांगजिंग प्रिंटिंग कं. लि.
 3. नांजिंग बेवे इंटल. ट्रेडिंग कं. लि.
 4. हेके पैकिंग एंड प्रिंटिंग प्लांट कं. लि.
 5. शंघाई किंग शो इंडस्ट्रियल कं. लि.
 6. गोंगझोऊ जिंगुआं प्रिंटिंग कं. लि.
 7. वुई दादी प्रिंटिंग कं. लि.
 8. डोंगुआं फुशेंग प्रिंटिंग कं. लि.
 9. युआओ फीफेन लीजर एंड एंटरटेनमेंट गुड्स कं. लि.
 10. डोंगुआं डोंग होंग प्रेसवर्क लिमिटेड
- च. संबंधित देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया।
- छ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबंधित सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:
1. वेस्टर्न ग्रीनविल्ले कंपनी
 2. प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी
 3. मिरियाड होलिंग्स
 4. मिल्स रिटेल
 5. पोकर स्टाफ इंडिया
 6. आदिश्वर इम्पेक्स प्रा. लि.
- ज. संबंधित सामानों के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। तथापि, निम्नलिखित आयातकों ने जांच की अवधि के दौरान अनुरोध/टिप्पणियां दायर की हैं:
1. जेन इम्पेक्स
 2. वेलोसिटी
 3. सन सीज ट्रेडिंग कंपनी
 4. मैट्रो कार्ड एंड प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड

5. सन इंटरनेशनल

6. जैनिको ट्रेडर्स

7. ए जे इम्पेक्स

- झ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुली रखी सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर वर्तमान प्रकटन विवरण में ध्यान रखा गया है।
- ञ. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
- ट. इसके अतिरिक्त, आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी।
- ठ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है या जांच में काफी बाधा डाली है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम रिकार्ड किए गए हैं।
- ड. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे यहां "एनआईपी" कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उसे निर्मित करने तथा उसकी बिक्री करने की लागत पर आधारित है।
- ढ. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था और केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर आवश्यक संशोधन के साथ, जहां भी लागू हो, विश्वास किया गया है।
- ण. जांच 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2016(18 माह) (जिसे यहां आगे "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) की अवधि के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2012-13, 2013-14, 2014-15, और जांच की अवधि है।
- त. याचिकाकर्ताओं ने आईबीआईएस से लिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटन का आरोप लगाते हुए याचिका प्रस्तुत की थी। तथापि, संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार व्यौरे उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- थ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 30 जनवरी, 2018 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी प्रदान किए। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों को लिखित रूप में दायर करें। पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां ले लें तथा उनसे अनुरोध किया गया था कि अपने प्रत्युत्तर 12 फरवरी, 2018 तक प्रस्तुत करें।
- द. जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क और उपलब्ध कराई गई सूचना, जिस सीमा तक वे साक्ष्य का समर्थन करते हैं तथा वर्तमान जांच में संगत मानी गई है, प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार में लाई गई हैं।
- ध. एक प्रकटन विवरण 20.02.2018 को जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्य थे और प्रकटन विवरण के संबंध में यदि कोई टिप्पणियां हैं तो वे देने के लिए 26.02.2018 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों पर समुचित रूप से विचार किया है।
- न. अमेरिकी डॉलर से भारत रुपए में परिवर्तन के लिए विनिमय दर जांच की अवधि के लिए सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, 66.53 भारतीय रुपए के रूप में मानी गई है।
- प. इस अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. घरेलू उद्योग और आयातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में किए गए अनुरोध संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "प्लेइंग कार्ड" है। प्लेइंग कार्ड सामान्यतया विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलने के लिए प्रयुक्त, कागज या पीवीसी से बनाए गए 52 आयताकार पतले कार्ड के पैक हैं। प्लेइंग कार्ड में संख्याओं का क्रम होता है और सामने डायमंड, हार्ट, क्लब अथवा स्पेट जैसे प्रतीक चिह्न होते हैं, परंतु पिछली तरफ समान डिजाइन होता है। 52 प्लेइंग कार्ड का एक पूरा सेट एक पैक अथवा एक डैक अथवा एक सेट कहा जा सकता है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग अवसर एवं कौशल के विभिन्न खेलों को खेलने में किया जाता है। उनका प्रयोग भ्रम, कार्डिस्ट्री, कार्ड संरचना बनाने, कार्टोमेंसी तथा मैमोरी स्पोर्ट के लिए भी किया जाता है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद 9504 40 00 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, ये आयात कुछ अन्य आईटीसी एचएस कोड जैसे 3923 90 90, 3926 10 19, 3926 40 49, 3926 90 99, 4818 90 00, 4821 90 90, 4901 10 10, 4901 10 90, 8523 21 00, 9403 89 00, 9404 90 99, 9503 00 30, 9503 00 90, 9504 90 10, 9504 90 90, 9505 90 90, 9506 91 90, 9506 99 90 और 98049000 भी पाए गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- घ. जेन इम्पेक्स, वेलोसिटी और सन सीज ट्रेडिंग, मैट्रो कार्ड्स एंड प्रिंटर्स, सन इंटरनेशनल, जैनिको ट्रेडर्स और ए जे इम्पेक्स ने प्रभावली का उत्तर दायर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों में विचाराधीन उत्पाद के वर्गीकरण के लिए कोई मानदंड नहीं सुझाए हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने जांच से भटकाने के लिए ही अपने अनुरोध किए हैं।
- ङ. प्लेइंग कार्ड्स को विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों में वर्गीकृत करने के लिए कोई मानक मानदंड उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि आयात सांख्यिकी में दिया गया उत्पाद विवरण भी विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों में वर्गीकृत करने के लिए कोई उपयुक्त मानदंड नहीं दर्शाता। इससे घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से पहुँच मूल्य की श्रेणी वार/ग्रेड वार तुलना प्रभावित हुई है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यह याचिका विचाराधीन उत्पाद को प्लेइंग कार्ड्स के रूप में एक उत्पाद के रूप में परिभाषित करती है। उससे ज्यादा भ्रामक कुछ नहीं है। विचाराधीन उत्पाद की कई किस्में हैं और सभी प्रकार के प्लेइंग कार्डों को एक ही रूप में नहीं माना जा सकता। समर्थकों और याचिकाकर्ताओं की कीमत सूची का एक विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्लेइंग कार्डों के लिए कम से कम 62 प्रकार की कीमतें हैं। साथ ही कार्डों की न्यूनतम से अधिकतम कीमत के बीच कीमत दर 1983 प्रतिशत तक है। तार्किक रूप से प्लेइंग कार्डों की एक किस्म के लिए इतनी अधिक कीमत की किस्में नहीं हो सकतीं।
- ख. याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य को कम आंकने की मांग की है कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के अंतर्गत कई किस्म के उत्पाद हैं। याचिकाकर्ताओं को, यदि उत्पाद की केवल दो किस्में हैं तो इतनी सारी विभिन्न कीमतें रखने के कारण स्पष्ट करने चाहिए। यह सिद्ध है कि उत्पाद दो प्रकार का नहीं है। यह उत्पाद कई किस्म का है।
- ग. याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए पीसीएन की पहचान न किए जाने के औचित्य की मांग की है कि उससे कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यदि याचिकाकर्ताओं ने पीसीएन की पहचान की होती। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता इस बात से सहमत हैं कि उपलब्ध आयात की गुणवत्ता और मात्रा की उपलब्ध सूचना शामिल आयात किस्मों की पहचान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
- घ. यदि मामला वह है तो प्राधिकारी को अपर्याप्त साक्ष्य की मौजूदगी का निष्कर्ष निकालना होगा और सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के सिद्धांतों को लागू नहीं करना होगा। ग्वाटेमाला सीमेंट II और बेड लिनन के संबंध में डब्ल्यूटीओ प्राधिकारी निकाय की रिपोर्ट का संदर्भ दिया जाता है और वहां उस पर विश्वास किया जाता है जहां यह माना गया था कि प्राधिकारी को जांच की शुरुआत से पूर्व साक्ष्यों की पर्याप्तता और परिशुद्धता तथा साक्ष्यों की पर्याप्तता की जांच करना अपेक्षित है और साक्ष्यों की पर्याप्तता जांच की शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपेक्षित है। सूचना की पर्याप्तता और परिशुद्धता के आधार पर वर्तमान जांच रद्द किए जाने की आवश्यकता है।
- ङ. एल्यूमीनियम फॉइल, इलास्टोमेरिक यार्न, रेडिएटर, अलॉय व्हील्स, नॉन ओवन फैब्रिक, इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जैसी जांचें हैं जिनमें प्राधिकारी ने पीसीएन बनाने के लिए घरेलू उद्योग को निर्देश दिए और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया तथा उसके बाद हितबद्ध पक्षकारों से टेप्पणियां भी मांगीं।

- च. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के पास विचाराधीन उत्पाद की कई गुणवत्ताएं और किस्में होने के बावजूद पीसीएन बनाने के लिए पर्याप्त समय था। फिर भी, याचिकाकर्ता पीसीएन नहीं बना पाए और इस प्रकार एक-एक करके तुलना नहीं है।
- छ. याचिकाकर्ता आयात आंकड़ों को समुचित रूप से अलग करने में विफल रहे। कई मर्चें, जो गैर-विचाराधीन उत्पाद हैं, परंतु उनके द्वारा दायर आयात आंकड़ों में विचाराधीन उत्पाद के रूप में चिह्नित हैं। चिल्ड्रन प्लेइंग कार्ड्स, गेम्स, प्लेइंग कार्ड्स खिलाईने, कार्डबोर्ड चिल्ड्रन प्लेइंग गेम, गेम पाँकर बॉक्स आदि जैसी मर्चें विचाराधीन उत्पाद के रूप में मानी गई हैं।
- ज. आयात विभिन्न मापों की यूनिट के तहत आ रहे हैं, जैसे बॉक्स, दर्जन, ग्राम, किलोग्राम, संख्या, पैकेट, सेट, यूनिट आदि। याचिकाकर्ताओं ने माप की इकाई दर्जन के रूप में ली है। याचिका में माप की दूसरी इकाई को दर्जन में बदलने के लिए सिद्धांत कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "प्लेइंग कार्ड्स" है।
8. प्लेइंग कार्ड सामान्यतया विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलने के लिए प्रयुक्त, कागज या पीवीसी से बनाए गए 52 आयताकार पतले कार्ड के पैक हैं। प्लेइंग कार्ड में संख्याओं का क्रम होता है और सामने डायमंड, हार्ट, क्लब अथवा स्पेट जैसे प्रतीक चिह्न होते हैं, परंतु पिछली तरफ समान डिजाइन होता है। 52 प्लेइंग कार्ड का एक पूरा सेट एक पैक अथवा एक डैक अथवा एक सेट कहा जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग अवसर एवं कौशल के विभिन्न खेलों को खेलने में किया जाता है। उनका प्रयोग भ्रम, कारडिस्ट्री, कार्ड संरचना बनाने, कार्टोमेंसी तथा मैमोरी स्पोर्ट के लिए भी किया जाता है।
9. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद 9504 40 00 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, ये आयात कुछ अन्य आईटीसी एचएस कोड जैसे 3923 90 90, 3926 10 19, 3926 40 49, 3926 90 99, 4818 90 00, 4821 90 90, 4901 10 10, 4901 10 90, 8523 21 00, 9403 89 00, 9404 90 99, 9503 00 30, 9503 00 90, 9504 90 10, 9504 90 90, 9505 90 90, 9506 91 90, 9506 99 90 और 98049000 भी पाए गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
10. प्लेइंग कार्ड की विभिन्न किस्में में महत्वपूर्ण कीमत के अंतर, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा जारी कीमत सूची में दिखाई दे रहा है, के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो घरेलू उद्योग और न ही आयातकों ने विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों में करने के लिए किसी मानदंड का सुझाव दिया है।
11. प्लेइंग कार्ड्स को विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों में वर्गीकृत करने के लिए कोई मानक मानदंड उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि आयात सांख्यिकी में दिया गया उत्पाद विवरण भी विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों में वर्गीकृत करने के लिए कोई उपयुक्त मानदंड नहीं दर्शाता।
12. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क था कि याचिकाकर्ता ने सभी प्रकार के उत्पादों को एक श्रेणी में मिलाया है, अतः उत्पादों की कोई समुचित तुलना नहीं की गई है। दूसरे शब्दों में, कोई एक-एक करके तुलना नहीं थी। यदि समुचित तुलना की गई होती तो इतना अधिक पाटन मार्जिन और कीमत कटौती संभव नहीं थी।
13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्विवाद है कि यह उत्पाद विभिन्न उत्पाद किस्मों में उत्पादित किया जाता है और इसे आगे श्रेणीबद्ध किया जा सकता था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित उत्पाद वर्गीकरण के लिए मानदंड घरेलू उद्योग द्वारा विवादित नहीं थे। घरेलू उद्योग ने इसके बजाए यह तर्क दिया कि वह अनावश्यक है। चूंकि, शामिल उत्पाद की विभिन्न किस्मों की कीमत और अलग-अलग लागत के संबंध में रिकार्ड में कोई सूचना नहीं है, अतः प्राधिकारी आयात कीमत के भारित औसतों के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं।

घ. घरेलू उद्योग और उसका आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान 59 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, समर्थकों सहित याचिकाकर्ताओं का हिस्सा प्लेइंग कार्ड्स के कुल भारतीय उत्पादन का 91 प्रतिशत है। तदनुसार, याचिकाकर्ता आधार की आवश्यकता स्पष्ट रूप से पूरी करते हैं और इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार संबंधित उत्पाद के लिए भारत में "घरेलू उद्योग" हैं तथा संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए इस याचिका को लाने हेतु वे पूरी तरह सक्षम हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यह याचिका इंडियन प्लेइंग काइर्स मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन लिमिटेड की ओर से दायर की गई है जिसके 23 सदस्य हैं, उनमें से 3 सदस्य याचिकाकर्ता हैं और अन्य 7 सदस्यों ने इस याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग को स्पष्ट रूप से लिया है।
- ख. भारत के अन्य भागों में संबंधित उत्पाद के कई विनिर्माता हैं जो इस एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं। दिल्ली में प्लेइंग काइर्स के लगभग 50-80 उत्पादक हैं। उनमें से कोई भी इस याचिका के भाग नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं का इन विनिर्माताओं को जोड़े बिना कुल भारतीय उत्पादन के "प्रमुख अनुपात" के रूप में पर्याप्त आधार नहीं है।
- ग. संबद्ध सामानों के अन्य विनिर्माताओं के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। यह याचिका उद्योग में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर दायर की गई है।
- घ. प्राधिकारी को जांच की शुरुआत के चरण में संबद्ध सामानों के सभी विनिर्माताओं पर विचार करने का अवसर कभी नहीं था। इस प्रकार, प्राधिकारी के पास जांच की शुरुआत के स्तर पर भारतीय उत्पादन के संबंध में पूरे आंकड़े नहीं थे, पूरी जांच यह मानते हुए रद्द किए जाने की अपेक्षा है कि आधार के संबंध में जांच की शुरुआत के समय सूचना अत्यधिक रूप से अपूर्ण ही नहीं थी, बल्कि अत्यधिक झूठी और अत्यधिक भ्रामक भी थी।
- ङ. पाटनरोधी नियमावली का नियम 5 विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा, घरेलू उद्योग का आधार एवं क्षेत्र, पाटन का साक्ष्य, क्षति का साक्ष्य, कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य के संबंध में जांच की शुरुआत के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी के कुछ दायित्व लगाता है। यद्यपि, पाटन के साक्ष्य, क्षति के साक्ष्य, कारणात्मक संपर्क के साक्ष्य जैसे अनिवार्य मानदंडों के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर्याप्त हो सकती है। तथापि, आधार के पहलुओं के संबंध में अंतिम उदाहरण किए जाने की आवश्यकता है।
- च. चूंकि प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की अपेक्षा होती है कि आवेदन पत्र घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दिया गया है तथा तब तक कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी, जब तक नियमावली के तहत निर्धारित आरंभिक आवश्यकता पूरी नहीं की जाती तथा यदि कानून के तहत आरंभिक आवश्यकता पूरी की जाती है तो आवेदन पत्र दिया गया माना जाएगा, यह सिद्ध है कि निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में प्राधिकारी द्वारा किए जाने की आवश्यकता है तथा यह निर्धारण जांच की शुरुआत में पूर्णतः प्राप्त करे। यदि बाद में यह पाया जाता है कि याचिका में सूचना पूरी तरह अपूर्ण, अपर्याप्त, झूठी और भ्रामक थी तो जांच की शुरुआत के समय किया गया आधार कानून में विक्रित, दोषपूर्ण और बुरा है। इस आधार पर ही जांच को रद्द किए जाने की आवश्यकता है।
- छ. कई उच्च न्यायालय के आदेशों में यह माना गया है कि आधार का अंतिम निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में किए जाने की अपेक्षा है और जांच परिणाम के चरण में निर्धारण के लिए खुला नहीं है। अन्यथा भी याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के समय यह सही-सही स्वीकार किया है कि सूचना जानकारी और विश्वास के आधार पर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह माना कि वे संबद्ध सामानों के अन्य उत्पादकों को शामिल किए बिना घरेलू उद्योग का प्रमुख अनुपात है।
- ज. याचिकाकर्ताओं ने इंडियन प्लेइंग काइर्स मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन लिमिटेड की सूचना के आधार पर अपने आधार के औचित्य की मांग की है। हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह आश्चर्य की बात है कि एसोसिएशन की कोई वेबसाइट नहीं है और एसोसिएशन के सदस्यों के संबंध में कोई ब्यौरे नहीं हैं। यह एसोसिएशन और उसके सदस्यों के विश्वास के संबंध में गंभीर संदेह बनाता है।
- झ. एसोसिएशन का कोई भी सदस्य इस तथ्य के बावजूद दिल्ली आधारित नहीं है कि दिल्ली में प्लेइंग काइर्स विनिर्माताओं के बहुत सदस्य हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समय घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

17. आवेदन पत्र मैसर्स पार्कसन्स ग्राफिक्स प्रा. लि., मैसर्स पार्कसन्स कार्टामुंडी प्रा. लि. और मैसर्स टी एम प्रिंटर्स प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। इस याचिका का निम्नलिखित द्वारा भी समर्थन किया गया है:

- 1) जेएमके इंटरप्राइजेज
- 2) कगलवाला पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
- 3) एलकेएम इंटरप्राइजेज
- 4) नंदी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
- 5) अजंता प्रिंट आर्ट्स
- 6) बथीजा इंटरप्राइजेज
- 7) टी. एम. इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व टी एम इंटरप्राइजेज)

18. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनका क्षति की अवधि में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय उत्पादन पर नियंत्रण (55 प्रतिशत से 59 प्रतिशत) है। हितबद्ध पक्षकारों ने याचिकाकर्ता के दावे पर विवाद किया है और तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के 75 से 80 उत्पादक हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के भारी संख्या में उत्पादक हैं जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा पूरी तरह छिपाए गए हैं। प्रकटन विवरण जारी करने के बाद मैसर्स दिल्ली प्लेइंग कार्ड एसोसिएशन, जिनका पता 5740, प्रथम तल, गांधीनगर, सदर बाजार, दिल्ली है, ने प्राधिकारी को यह कहते हुए लिखा है कि कई उत्पादक विगत में 10 से 14 क्षेत्र में पूर्व में हुआ करते थे, परंतु उत्पादित न होने वाले आयातों के कारण अधिकतर उत्पादकों ने काम बंद कर दिया है। तथापि, कोई सत्यापनीय सूचना, न तो विगत में उत्पादकों के नाम की, अथवा जिन उत्पादकों ने आयातों के कारण उत्पादन बंद कर दिया है, इस एसोसिएशन को कोई सूचना नहीं दी है। यहां तक कि उत्पाद के उत्पादकों के नाम उस पत्र में इस एसोसिएशन द्वारा उल्लिखित नहीं किए गए हैं।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसोसिएशन ने उसकी मौजूदगी के संबंध में न तो कोई सूचना दी है और न ही उत्तरी क्षेत्र में उन उत्पादकों के ब्यौरे दिए हैं जो इसके सदस्य हैं अथवा उत्तरी क्षेत्र में उन उत्पादकों के ब्यौरे दिए हैं जो प्लेइंग कार्ड्स के विनिर्माता हैं। प्राधिकारी को उसके पंजीकृत/मान्यताप्राप्त निकाय होने की मौजूदगी के संबंध में कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

20. याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि प्लेइंग कार्ड्स के कई विनिर्माता अब विचाराधीन उत्पाद के आयातक हो गए हैं और यह अनुरोध किया कि मैसर्स मैट्रो कार्ड एंड प्रिंटर्स पूर्व में प्लेइंग कार्ड्स का विनिर्माण कर रहा था और आयातक हो गया है। तथापि, मैसर्स मैट्रो कार्ड एंड प्रिंटर्स के नाम वाला कोई अन्य उत्पादक याचिकाकर्ता द्वारा नहीं पहचाना गया है जो अब आयातक हो गया हो। मैसर्स मैट्रो कार्ड एंड प्रिंटर्स ने यह उल्लेख करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया है कि कंपनी ने 2006 में अर्थात् एक दशक से अधिक पीछे से उत्पादन रोक दिया था। कंपनी ने यह भी उल्लेख किया है कि संयंत्र पाटित आयातों के अलावा अन्य कारणों से (प्रबंधन की बड़ी हुई आयु तथा भिन्न-भिन्न कैरियर करने वाले पारिवारिक सदस्यों के विनिर्माण प्रचालनों की सार-संभाल को जारी रखने में असमर्थता के कारण) बंद हो गया था। विशेषकर कंपनी ने अनुरोध किया कि उत्पाद का पाटन उत्पादों को बंद करने का कारण नहीं था और वस्तुतः इस उत्पाद के मुश्किल से ही उस समय कोई आयात थे जब कंपनी ने उत्पादन बंद कर दिया था।

21. प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट करते हैं और मानते हैं कि प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर आधार निर्धारित किया है।

22. याचिकाकर्ताओं के उत्पादन में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात है।

ग. गोपनीयता

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. नियम 7 के तहत सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं और ऐसा कोई उदाहरण उल्लिखित नहीं किया गया है जब याचिकाकर्ता ने वे आंकड़े उपलब्ध न कराए हों जिसके लिए हकदार नहीं थे।
- ख. दावा की गई गोपनीयता निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुमति की परिपाटी के अनुसार है। लागत संबंधी सूचना के लिए गोपनीयता की आवश्यकता होती है जो कि उसमें याचिकाकर्ता की अत्यधिक निजी व्यापारिक सूचना होती है।
- ग. हितबद्ध पक्षकारों ने फिर भी आयातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

24. गोपनीयता के दावों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

26. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो भी सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, उसे गोपनीय नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए।

घ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**सामान्य मूल्य**

27. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र से या किसी उपर्युक्त तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में यथा निर्धारित, प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि विभिन्न किस्मों के प्लेइंग कार्ड्स में कीमत का काफी अंतर होने की दृष्टि से, जैसा कि विचाराधीन उत्पाद के लिए याचिकाकर्ताओं और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा जारी की गई कीमत सूची में दिखाई देता है, एकल पाटन मार्जिन का निर्धारण, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन उपयुक्त नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

29. यह नोट किया जाता है कि चीन जन गण में संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। इसीलिए, प्राधिकारी ने धारा 9क(6क) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

चीन जन गण में उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

30. संबद्ध देश और किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध सामानों के लिए कोई विश्वसनीय कीमत एवं लागत के ब्यौरे न होने की स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समान उत्पाद के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य उपयुक्त लाभ मार्जिन पर निर्मित किया है। तदनुसार, चीन जन गण से संबद्ध सामानों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया गया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ड. निर्यात कीमत

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन गण से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। चीन जन गण में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध सामानों के लिए भारत औसत निर्यात कीमत निर्धारित की है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

पाटन मार्जिन

32. भारत में निर्यात कीमत की तुलना पाटन मार्जिन के निर्धारित करने के लिए सामान्य मूल्य के साथ की गई है। संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, जैसा कि निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

विवरण	यूनिट	डीजीसीआईएस आयात आंकड़ों पर आधारित
सामान्य मूल्य	अमेरिकी डॉलर प्रति दर्जन	***
कारखानागत निर्यात कीमत	अमेरिकी डॉलर प्रति दर्जन	***
पाटन मार्जिन	अमेरिकी डॉलर प्रति दर्जन	***
	%	***
	रेंज	330-340

33. यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन काफी हैं और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

च. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क का निर्धारण

34. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..."। "ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

35. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

घरेलू उद्योग के विचार

36. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति संबंधी मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. जांच की पूरी अवधि में संबद्ध सामानों का आयात पूर्ण रूप में बढ़ा है। संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात पूरी तरह से बढ़ा है।

ख. संबद्ध सामानों का आयात उत्पादन के संबंध में और भारत में खपत के संबंध में भी बढ़ा है।

- ग. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है, यहां तक कि संबद्ध सामानों के लिए मांग भारत में बढ़ती रही है। यह इस कारण है कि आयातों में मांग में वृद्धि आक्रामक रूप से हुई है और संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा 2012-13 से जांच की अवधि (क) तक काफी बढ़ा है।
- घ. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।
- ङ. घरेलू उद्योग की मालसूची काफी बड़ी है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। आयातों के कारण भारत में मांग आक्रामक रूप से बढ़ती रही है।
- च. भारत में आने वाले कम कीमत के पाटित आयातों के कारण काफी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है।
- छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और लगाई गई पूंजी पर आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लाभप्रदता पूरी क्षति जांच की अवधि में नकारात्मक रही है क्योंकि पूरी क्षति जांच अवधि में आयात काफी कम कीमतों पर आते रहे हैं।
- ज. घरेलू उद्योग का निष्पादन लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह की दृष्टि से काफी प्रतिकूल था। घरेलू उद्योग उत्पाद के लिए क्षति रहित कीमत वसूल करने में समर्थ नहीं हैं।
- झ. यह विश्लेषण गहनता से यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को भारत में विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते हुए पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध सामानों के पाटित आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के बीच प्रबल संबंध है।

घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावों के संबंध आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुसार निम्नलिखित हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेड हैं और सही तुलना सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ताओं को किस्म वार तुलना करनी चाहिए थी। याचिकाकर्ताओं का ब्रोशर स्वयं ही भारी कीमत की रेंज में विभिन्न उत्पाद किस्मों दर्शाता है। अतः एकत्रित आधार पर कीमत कटौती भ्रामक है और उसे घरेलू उद्योग को क्षति के निर्धारण के लिए आधार नहीं माना जा सकता।
- ख. संबंधित उत्पाद की विभिन्न किस्मों में कोई समग्र तुलना भ्रामक है। यह स्वीकार न करते हुए कि आयात की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है, घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता बढ़ाने में सक्षम है।
- ग. यह देखना रोचक है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री की लागत से अधिक बढ़ी है। वस्तुतः जांच की अवधि में बिक्री की लागत अपरिवर्तित रही है और बिक्री की कीमत काफी बढ़ी है जो यह दर्शाता है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर कोई ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव नहीं पड़ा है।
- घ. याचिकाकर्ताओं द्वारा परकलित इतना अधिक पाटन मार्जिन अत्यधिक भ्रामक है। विचाराधीन उत्पाद के भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रेड हैं और ग्रेड वार तुलना होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने आयातों की न्यूनतम कीमत की तुलना अपने अधिकतम गुणवत्ता वाले उत्पाद के साथ की है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने आयात कीमत का गलत परिकलन किया है।
- ङ. यह सिद्ध है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में आवेदन पत्र में उपलब्ध सूचना आयात कीमत के संबंध में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी।
- च. ऐसी स्थिति में, जहां आयात आंकड़े निर्यात कीमत को पर्याप्त रूप से सिद्ध करने में अपर्याप्त हैं, वहां प्राधिकारी को अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना और उत्पाद की पुनः बिक्री कीमत जैसे साक्ष्यों पर विश्वास करना चाहिए। उत्पाद की वह पुनः बिक्री कीमत आयातकों द्वारा पुनः बेचे गए आयातित उत्पाद की कीमत सूची पर विचार कर तैयार रूप में सिद्ध की जा सकती है।
- छ. विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मौजूदगी भारित औसत विश्लेषण की अनुप्रयुक्तता भी सिद्ध करती है कि निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं का तर्क पर्याप्त है। यह भी सिद्ध है कि याचिकाकर्ताओं ने यह विश्वास करने में प्राधिकारी को पूर्ण रूप से भ्रमित किया कि आयात कीमत निर्धारित करने के लिए सूचना उपलब्ध नहीं थी।
- ज. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ग्रेड वार कीमतें, उतनी न्यूनतम जितनी याचिकाकर्ताओं के लिए करना अपेक्षित है, निर्धारित करने के लिए आयात कीमतें काफी अपर्याप्त हैं, वैकल्पिक आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए है।
- झ. निर्यात कीमत की परिभाषा यह दर्शाएगी कि यदि आयात कीमत विभिन्न उत्पाद किस्मों, जिन्हें आयात आंकड़ों में नहीं पहचाना जा सकता, की मौजूदगी सहित किसी भी कारण से अविश्वसनीय प्रतीत होती है तो प्राधिकारी को वैकल्पिक साधनों पर विचार करने की अपेक्षा है।
- ञ. याचिकाकर्ताओं का याचिका के चरण में ग्रेड वार विश्लेषण प्रस्तुत न करने में दुर्भावपूर्ण इरादा था। हॉट एवं कोल्ड रोलड कार्बन स्टील के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच का संदर्भ लेना संगत होगा जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र में

पीसीएन सिद्धांत अभिज्ञात किया था, परंतु पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उसकी उपेक्षा की थी। अंतिम जांच परिणाम के स्तर पर भी याचिका के चरण में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित पीसीएन की उपेक्षा करने में प्राधिकारी मजबूर थे।

ट. इस प्रकार, यह सिद्ध है कि वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ताओं ने (क) पीसीएन की पहचान न करने, (ख) जांच की शुरुआत की मांग करने, (ग) मुद्दे को उठाने के लिए हितबद्ध पक्षकारों की प्रतीक्षा करने तथा (घ) उसके बाद यह तर्क देने कि निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया है, की समान नीति अपनाई है। इस तथ्य कि निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया है, का पीसीएन की पहचान की आवश्यकता के संबंध में कोई अर्थ नहीं है। निर्यातक भी केवल इस विसंगति के कारण सहयोग नहीं कर पाए कि याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में झांकने की अनुमति दे दी थी।

ठ. प्राधिकारी को इस्पात के मामले के समान नीति/तरीके अपनाने से याचिकाकर्ताओं को रोकना चाहिए जिसमें स्वयं याचिकाकर्ताओं द्वारा पीसीएन की पहचान किए जाने के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी उस समय भी निर्धारण के चरण में उसकी उपेक्षा करने के लिए मजबूर थे जब हितबद्ध पक्षकारों ने उस जांच में सहयोग किया था।

ड. ऐसी स्थिति में जब प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि याचिका में अपर्याप्त सूचना/ साक्ष्य थे तो याचिका के चरण में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के सिद्धांतों को नहीं लगाया जा सकता और उसके बजाए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि याचिका में जांच की शुरुआत का औचित्य दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य का अभाव था।

ढ. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी को प्रस्ताव किया था कि यदि क्षति/हानियां होती हैं तो इसका अर्थ है कि उसमें सभी आर्थिक कारकों का मूल्यांकन और उद्योग की स्थिति में बाधा डालने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा जिसमें घरेलू उद्योग के सभी मात्रात्मक और कीमत संबंधी मानदंडों में स्वाभाविक और संभावित गिरावट शामिल होगी तथा स्वतंत्र रूप से क्षति सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। तथापि, यह सिद्ध है कि पाटित आयातों और क्षति के बीच "और" शब्द रखना दोनों स्थितियों में साथ-साथ मौजूद रहना चाहिए और इनमें से किसी का सिद्ध होना ही प्राधिकारी के यह निष्कर्ष निकालने से पूर्व अपर्याप्त है कि उत्पाद के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ण. ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने की अपेक्षा है कि क्या पाटित आयातों के अलावा कोई ज्ञात कारक साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं और इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों में यह शर्त बिल्कुल भी मौजूद नहीं है।

त. याचिकाकर्ताओं को जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार करना अपेक्षित है और यह सिद्ध करना भी अपेक्षित है कि क्या वे यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादन पिछले वर्षों के निष्पादन की तुलना में इस निष्पादन पर ध्यान देते हुए "क्षति कारक" था।

थ. (क) आधार वर्ष के संदर्भ में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन, (ख) आधार वर्ष के अगले वर्ष के संदर्भ में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन (परवर्ती वर्ष), और (ग) पिछले वर्ष के संदर्भ में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन (ठीक पूर्व वर्ष) पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग का निष्पादन। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि क्या वर्तमान जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन की आधार वर्ष, परवर्ती वर्ष और ठीक पूर्व वर्ष के साथ की जाती है, घरेलू उद्योग का निष्पादन कोई ह्रास नहीं दर्शाता।

द. आधार वर्ष से जांच की अवधि, पूर्व वर्ष से जांच की अवधि और परवर्ती वर्ष से जांच की अवधि से प्रवृत्ति उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, स्टॉक और क्षमताओं के संबंध में कोई ह्रास नहीं दर्शाती।

ध. लाभ, नकद प्रवाह और घरेलू उद्योग का आरओआई के संबंध में प्रवृत्तियां कोई ह्रास नहीं दर्शातीं, भले ही उनकी तुलना आधार वर्ष से जांच की अवधि, पूर्व वर्ष से जांच की अवधि तथा परवर्ती वर्ष से जांच की अवधि में की जाए।

न. जिस अवधि के लिए निष्पादन की तुलना की जाती है, उसको ध्यान में न रखते हुए (क) क्षमता उपयोग, (ख) बाजार हिस्सा और (ग) मालसूची को छोड़कर घरेलू उद्योग के निष्पादन में कोई ह्रास नहीं है। इन मानदंडों का नीचे समाधान किया गया है और यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग इन कारणों से भी क्षति का दावा नहीं कर सकता।

प. क्षमता, क्षमता उपयोग एवं मांग में प्रवृत्तियां। यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि सूचित की है। क्षमताओं में यह वृद्धि मौजूदा क्षमताओं के पूर्णतः अनुपयुक्त रहने के बावजूद है। इस प्रकार, जब मौजूदा क्षमताएं इतनी अधिक अनुपयुक्त थीं तो घरेलू उद्योग के पास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोई औचित्य नहीं था। परंतु घरेलू उद्योग ने ऐसा किया।

फ. क्षमता उपयोग में गिरावट उत्पादन में वृद्धि के बावजूद है और इसीलिए क्षमताओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप है। यदि क्षमता बढ़ाई जाती है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव स्वाभाविक रूप से क्षमता उपयोग पर पड़ेगा, विशेष रूप से जब मौजूदा क्षमताएं पूर्ण रूप से अनुपयुक्त हों।

ब. क्षमता में वृद्धि एक याचिकाकर्ता की क्षमता में वृद्धि के कारण है। क्षमता उपयोग में थोड़ी सी गिरावट है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने कम उपयुक्त मौजूदा क्षमताओं के बावजूद क्षमताएं बढ़ाई हैं।

भ. याचिकाकर्ता क्षति के मानदंड के रूप में बाजार हिस्से में गिरावट का दावा करते हैं। किसी भी तरह घरेलू उद्योग यह दावा नहीं कर सकता कि उन्होंने इतने वास्तविक रूप से बाजार हिस्सा खोया है कि उसे "वास्तविक क्षति" मानने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जब बाजार हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति उपर्युक्त हो। बाजार हिस्से में केवल 2 प्रतिशत की गिरावट पूर्णतः अपर्याप्त है और यह उसके परिणामस्वरूप हो सकती है कि कितने आयातों की पर्याप्त रूप से पहचान की गई।

म. अकेले इस मानदंड के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए बाजार हिस्से में काफी गिरावट होनी चाहिए कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, विशेष रूप से जब घरेलू उद्योग का पूरा मामला इस गिरावट पर आधारित है।

य. मालसूची में वृद्धि याचिकाकर्ताओं द्वारा शामिल किए गए अन्य नए उत्पादों के कारण हो सकती है। यह मालसूची में वृद्धि का मामला नहीं है। यह पूर्णतः स्वाभाविक है कि घरेलू उद्योग को क्रेताओं को उत्पाद का पूर्ण स्वरूप पेश करने में विभिन्न उत्पाद किस्मों के लिए और मालसूची की उपयुक्त मात्रा रखना अपेक्षित है। इस प्रकार, मालसूची में वृद्धि उत्पाद के पाटन के परिणामस्वरूप नहीं है। मालसूची में वृद्धि क्षमताओं में वृद्धि तथा नई उत्पाद किस्मों को शामिल करने का परिणामी प्रभाव है।

कक. आयात का पैटर्न कीमत झुकाव के आधार पर है। यह देखा जाएगा कि आयात बहुत ही काफी कीमत झुकाव में सूचित किए गए हैं। विभिन्न उत्पाद किस्मों में शामिल हैं जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा सूचित किया गया है। वस्तुतः याचिकाकर्ता और ये आयात विभिन्न बाजार क्षेत्रों में मौजूद हैं। यह याचिकाकर्ता के उत्पाद की कीमत सूची की अन्य पक्षकारों द्वारा तथा दिल्ली आधारित उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के साथ तुलना द्वारा सिद्ध हो जाता है।

खख. कीमत सूची में काफी अंतर स्पष्ट रूप से विभिन्न उत्पादों की मौजूदगी दर्शाता है। चीन से आयातित उत्पाद वास्तव में दिल्ली आधारित उत्पादकों द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति किए गए उत्पाद से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। यह याचिकाकर्ताओं के उत्पाद से प्रतिस्पर्द्धा नहीं करता। याचिकाकर्ता वस्तुतः विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालन कर रहे हैं और उनका उत्पाद उस बाजार क्षेत्र में नहीं बेचा जाता है जहां आयातित उत्पाद बेचे जा रहे हैं और जहां दिल्ली आधारित उत्पादक अपने उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं।

गग. याचिकाकर्ताओं ने उत्पाद में अंतर को कम दिखाने के लिए यह कहते हुए मांग की है कि आयात विवरण उत्पाद किस्म नहीं दर्शाता। यहां तक कि यदि यह माना जाए कि आयात आंकड़ों में उत्पाद किस्म की पहचान करना संभव नहीं है तो हमारा अनुरोध है कि याचिकाकर्ताओं और दिल्ली आधारित उत्पादकों द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए उत्पाद में शामिल उत्पाद किस्मों की पहचान करना संभव है। दिल्ली आधारित उत्पादकों की कीमतों और याचिकाकर्ताओं के उत्पाद में भारी अंतर यह दर्शाता है कि दोनों समान नहीं हैं।

घघ. कागज अथवा प्लास्टिक अथवा पीवीसी, ग्रामेज, लेमिनेटिड अथवा बिना लेमिनेटिड, रिसाइक्लिन पेपर अथवा वर्जिन पेपर जैसे मानदंडों से उत्पाद की लागत और कीमत शासित होती है तथा इसीलिए पीसीएन के विकास के लिए उन पर विचार किया जाना चाहिए।

डड. विभिन्न विनिर्माताओं की कीमत सूची यह दर्शाती है कि ये विनिर्माता भयानक रूप से एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं और यह वह मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता आयातों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हों। वस्तुतः आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग के उत्पाद के बीच भारी कीमत अंतर यह दर्शाता है कि विभिन्न घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए उत्पाद बारी प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं जिससे याचिकाकर्ताओं को सतत रूप से वित्तीय हानियां हो रही हैं।

चच. याचिकाकर्ताओं की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि वे अपवादस्वरूप अच्छा निष्पादन कर रहे हैं और यह उनके सुधर रहे राजस्व, पीबीटी, पीबीआईटी और नकद लाभ में देखा जा सकता है।

छछ. आयातित चीनी उत्पाद मूल रूप से दिल्ली आधारित विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद से प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं जो कि कम गुणवत्ता के कागज वाले प्लेइंग कार्ड हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा बनाए गए प्लेइंग कार्ड उच्च गुणवत्ता के हैं और बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की पूर्ति करते हैं। आयातित सामान और याचिकाकर्ता के उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं और वे एक-दूसरे के साथ सीधी प्रतिस्पर्द्धा में भी नहीं हैं।

जज. हाल के बजट 2018-19 में प्लेइंग कार्डों पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। अब चूंकि आयात शुल्क दोगुना कर दिया गया है, अतः पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग के लिए दोगुने संरक्षण का कार्य करेगा। बड़े हुए आयात शुल्क से स्वतः ही कम आयात होगा और इस प्रकार घरेलू उद्योग के पास कोई कारण नहीं रह जाता तथा उसे वर्तमान जांच वापस लेनी चाहिए।

झझ. केवल आयात में वृद्धि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए आधार नहीं हो सकता। आयात मांग में वृद्धि के कारण बढ़े हैं। तथापि, घरेलू उद्योग को आयातों में वृद्धि के कारण क्षति नहीं हुई है।

प्राधिकारी द्वारा मुद्दों की जांच

38. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच की गई है और निम्नलिखित रूप में उनका समाधान किया गया है:

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के पहुँच मूल्य में गिरावट आई है।
- ख. घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूरा क्षति विश्लेषण याचिकाकर्ताओं के घरेलू निष्पादन पर ही आधारित है।
- ग. क्षति विश्लेषण परवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

पाटित आयातों का प्रभाव**पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव****मांग का मूल्यांकन**

39. संबद्ध सामानों की मांग समान उत्पाद के भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री को सभी देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में जोड़कर निर्धारित की गई है। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों की मांग में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है जो कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाई जा सकती है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
चीन जन गण से आयात	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	135	134	149
अन्य देशों से आयात	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	99	425	564
याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	108	108	113
समर्थकों की घरेलू बिक्री	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	112	115	126
अन्य उत्पादों की घरेलू बिक्री	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	91	87	83
कुल मांग	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	113	114	122

40. विचाराधीन उत्पाद के याचिकाकर्ताओं, समर्थकों और अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री निरंतर बढ़ी है।

आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

41. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या पूर्ण रूप से अथवा उत्पादन की तुलना में अथवा भारत में खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
चीन जन गण से आयात	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	135	134	149
अन्य देशों से आयात	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	99	425	564
कुल आयात	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	135	136	152
कुल मांग	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	113	114	122
भारत में खपत के संबंध में चीन जन गण से आयात	%	***	***	***	***
	रेंज	10-20	20-30	20-30	20-30
याचिकाकर्ताओं का उत्पादन	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	106	113
भारत में खपत के संबंध में चीन जन गण से आयात	%	***	***	***	***
	रेंज	40-50	50-60	50-60	50-60

42. प्राधिकारी उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात घरेलू उत्पादन की तुलना में चीन जन गण से काफी मात्रा में बढ़े हैं और सतत रूप से बढ़ रहे हैं तथा जांच की अवधि के दौरान 58 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गए हैं।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा खपत और उत्पादन की तुलना में चीन जन गण से आयात निरंतर बढ़े हैं।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

43. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, नियमावली का अनुबंध-II(ii) नीचे दिया गया है:

"जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।"

44. यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा में अन्यथा कीमत ह्रास करने के लिए है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के

लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

कीमत कटौती

45. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से की है। इस संबंध में, उत्पाद के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग की सभी छूटों और करों की निवल औसत बिक्री कीमत को व्यापार के विशेष स्तर पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया है। घरेलू कीमतों और कटौती का मार्जिन निम्नलिखित तालिका के अनुसार दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	अप्रैल, 2015 –सितंबर, 2016 (पीओआई)
आयातों की पहुँच कीमत	रुपए प्रति दर्जन	***
घरेलू बिक्री कीमत	रुपए प्रति दर्जन	***
कीमत कटौती	रुपए प्रति दर्जन	***
	%	***
	%रेंज	350-360

46. प्राधिकारी उपर्युक्त तालिका से नोट करते हैं कि काफी कीमत कटौती मौजूद है। तथापि, उपर्युक्त क्रम सं. 39 पर तालिका से देखा जाता है कि इतनी काफी कीमत कटौती के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री पूर्ण रूप से बढ़ी है जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग इतने अधिक पाटन मार्जिन और कीमत कटौती के बावजूद अपनी बिक्री बढ़ाने में समर्थ रहा है।

कम कीमत पर बिक्री

47. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कम कीमत पर बिक्री की जांच भी की है। इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना आयातों की पहुँच कीमत के साथ की गई है।

विवरण	यूनिट	डीजीसीआईएस आयात आंकड़ों पर आधारित
आयातों की कीमत	रुपए प्रति दर्जन	***
एनआईपी	रुपए प्रति दर्जन	***
कम कीमत पर बिक्री	रुपए प्रति दर्जन	***
	%	***
	% रेंज	360-370

48. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से काफी कम थी।

कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

49. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से काफी मात्रा में कीमतों का ह्रास हो रहा है अथवा कीमतों में वृद्धि रुक रही है जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागत एवं कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया। स्थिति निम्नलिखित तालिका के अनुसार दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल, 2015 – सितंबर, 2016 (पीओआई)
निर्माण और बिक्री की लागत	रुपए प्रति दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	118	119
घरेलू बिक्री कीमत	रुपए प्रति दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	114	121

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल, 2015 – सितंबर, 2016 (पीओआई)
पहुँच मूल्य	रुपए प्रति दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	105	120	134

50. यह नोट किया जाता है कि समान वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत बढ़ी है तथा उसकी बिक्री कीमत आनुपातिक रूप से बढ़ी है। आयातों की पहुँच कीमत भी बढ़ी है।

51. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि आंकड़े यह दर्शाते हैं कि प्राधिकारी की टिप्पणियाँ कि कोई न्यूनीकरण/ह्रास नहीं है, आधारहीन हैं। तथापि, यह देखा जाता है कि जबकि आयातों की पहुँच कीमत 33 प्रतिशत तक के औसत पर बढ़ी है तो घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें 21 प्रतिशत तक बढ़ी और बिक्री की लागत 19 प्रतिशत तक बढ़ी। इस प्रकार, घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बिक्री की लागत से अधिक बढ़ाने में समर्थ थे और साथ ही उसने अपनी कीमतें आयात की पहुँच कीमत में वृद्धि तक नहीं बढ़ाई। इस प्रकार, आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण/ह्रास नहीं हुआ है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

52. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:-

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

53. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित था:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	वार्षिकीकृत
कुल संस्थापित क्षमता	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	115	114
पार्कसन ग्राफिक्स	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	109	114
पार्कसन कार्टामुंडी	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
टीएम प्रिंटर्स	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	130	134	129
कुल उत्पादन	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	104	102	110
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	रेंज	50-60	50-60	50-60	50-60

54. तीन याचिकाकर्ताओं के लिए विचाराधीन उत्पाद की संस्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि ये मानदंड पूरी क्षति की अवधि में लगभग समान रहे हैं।

55. घरेलू उद्योग ने वास्तविक प्रतिशतता के बजाए दिए जा रहे क्षमता उपयोग की दर के संबंध में चिंताएं उठाई हैं। उसे ऊपर शामिल कर दिया गया है।

56. यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने उपयोग में न लाई गई क्षमताओं के अपने स्वीकृत दावों की बजाए क्षमताएं बढ़ाई हैं। 14 प्रतिशत तक क्षमता में वृद्धि और क्षमता विस्तार से पहले उपयोग में न लाई गई क्षमताओं की मौजूदगी के बावजूद जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का ही क्षमता उपयोग आंशिक रूप से बढ़ा, जब आधार वर्ष से उसकी तुलना की जाए

ii. लाभप्रदता

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल, 2015 – सितंबर, 2016 (पीओआई)	वार्षिकीकृत
पार्कसन ग्राफिक्स	रुपए लाख में	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	48	(379)	(1318)	879
पार्कसन कार्टामुंडी	रुपए लाख में	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(135)	(182)	(65)	(44)
टीएम प्रिंटर्स	रुपए लाख में	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	155	79	98	66
कुल लाभ	रुपए	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(46)	(556)	136	136
लाभ प्रति दर्जन	आईएनआर	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(43)	(513)	120	120

57. उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को 2013-14 के दौरान हानियां हुई हैं, परंतु उसके बाद जांच की अवधि के दौरान काफी लाभ हुए हैं। जांच करने पर लाभ का यह पैटर्न सीधे ही आयात कीमतों से सह संबंध नहीं बना सकता। अतः लाभप्रदता के साथ पाटित आयातों का कारणात्मक संपर्क स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं है।

iii. लगाई गई पूंजी पर आय

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल, 2015 – सितंबर, 2016 (पीओआई) वार्षिकीकृत
पीवीआईटी	रुपए लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	170	56	177
नियोजित पूंजी	रुपए लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	138	139	147
आरओसीई	%	***	***	***	***
	रेंज	5-15%	5-15%	0-10%	5-15%

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग क्षति की जांच की पूरी अवधि में लगाई गई पूंजी पर पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम रहा है।

59. इसके अतिरिक्त, ब्याज पूर्व लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ, दोनों जांच की अवधि के दौरान काफी अधिक रहे हैं।

iv. **बाजार हिस्सा**

60. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
कुल मांग	दर्जन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	113	114	122
का बाजार हिस्सा					
- याचिकाकर्ता	%	***	***	***	***
	रेंज	40-50	40-50	40-50	40-50
- समर्थक	%	***	***	***	***
	रेंज	20-30	20-30	20-30	20-30
- अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
	रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10
चीन जन गण से आयातों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	रेंज	20-30	20-30	20-30	20-30
अन्य देशों से आयात का हिस्सा	%	***	***	***	***
	रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10

61. प्राधिकारी यह देखते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा न्यूनतम रूप से कम हुआ है, फिर भी संबद्ध सामानों के लिए मांग भारत में बढ़ती रही है।

62. घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद की विक्री मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी है।

63. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के हिस्से में आंशिक रूप से 3 प्रतिशत तक कि गिरावट आई, जबकि समर्थकों का बाजार हिस्सा 1 प्रतिशत तक बढ़ा। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट काफी नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क कि भारी आयातों के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मरा, यह देखते हुए कि समर्थकों ने बाजार हिस्सा बढ़ाया है, मान्य नहीं है।

v. **मालसूची**

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल, 2015 – सितंबर, 2016 (पीओआई)
उत्पादन	दर्जन	7,582,777	7,851,7774	7,708,030	8,370,569
	सूचीबद्ध	100	104	102	110
औसत मालसूची	दर्जन	***	***	***	***
उत्पादन के दिनों के रूप में मालसूची		10	15	19	17
औसत मालसूची	सूचीबद्ध	100	151	182	179

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मालसूची संचित की है। मालसूची का स्तर पूरी क्षति की अवधि में बढ़ा है। तथापि, औसत दिवसों की संख्या, जिसके लिए घरेलू उद्योग स्टॉक में उत्पादन को रखे हुए था, का परिकलन किया गया। यह पाया गया है कि स्टॉक में उत्पादन के देशों की संख्या मानना अधिक नहीं है।

vi. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर जांच की अवधि के दौरान कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाता। इसके अतिरिक्त, प्रति कर्मचारी उत्पादकता अच्छी रही है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	115	137	114
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	90	74	145

पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने संयंत्र एवं मशीनरी में काफी निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, पाटित आयातों की बजाए संयंत्र एवं मशीनरी में बढ़े हुए निवेश के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना रिकार्ड में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार नकारी नहीं जा सकती।

पाटन का स्तर एवं पाटन मार्जिन

67. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर देश में आ रहे हैं और पाटन का मार्जिन काफी है।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

68. संबद्ध देश से आयात कीमतों की जांच, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों के सिवाय अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, समर्थक उत्पाद एवं आयात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में परिवर्तन, कीमत कटौती का स्तर, पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं करते कि संबद्ध देश से आयातित सामानों के पहुँच मूल्य से भारतीय बाजार में काफी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हो रही है। यद्यपि, क्षति की अवधि में आयात बढ़े हैं, याचिकाकर्ताओं और समर्थकों की बिक्री भी बढ़ी है तथा घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि से अधिक अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम रहा।

ख. क्षति के संबंध में समग्र विश्लेषण

69. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देते हुए तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयात पूर्ण रूप से तथा भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन और खपत की तुलना में बढ़े हैं। उत्पाद की आयात कीमतें संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत से कम हैं। उत्पाद के लिए मांग काफी बढ़ी है और चीन जन गण से आयातों का मांग में वृद्धि में भारी हिस्सा है। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और पूंजी पर आय जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ी है। मालसूची बढ़ी है, परंतु कर्मचारियों की संख्या भी उनकी उत्पादकता के साथ बढ़ी है।

ज. कारणात्मक संपर्क और अन्य कारक

70. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और पाटन के बीच कारणात्मक संपर्क की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है।

तीसरे देश से आयात

71. संबद्ध देश को छोड़कर देश से आयात मात्रा की दृष्टि से काफी नहीं हैं जो कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाए अथवा क्षति का खतरा पैदा करें। इसके अतिरिक्त, जिस कीमत पर अन्य देश से सामान आ रहे हैं, वह उस कीमत से काफी अधिक है जिस पर संबद्ध देश से सामान आ रहे हैं।

मांग में संकुचन

72. संबद्ध सामानों के लिए मांग ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है। तदनुसार, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती। वस्तुतः घरेलू उद्योग अपनी विक्री और बाजार हिस्सा मांग में वृद्धि के अनुरूप बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ और प्रतिस्पर्धा

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

प्रौद्योगिकी में विकास

74. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता।

खपत के पैटर्न में परिवर्तन

75. घरेलू उद्योग उस किस्म के उत्पादों का उत्पादन कर रहा है जो भारत में आयातित किए गए हैं। खपत के परिवर्तन में संभावित परिवर्तन ऐसे कारक नहीं हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति का दावा किया जा सकता हो।

निर्यात निष्पादन

76. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित काफी ह्रास के कारण नहीं है। वस्तुतः घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात वास्तविक रूप में कम नहीं हुए हैं।

अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग को निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन प्रभावित नहीं हुआ है। प्राधिकारी द्वारा जिस सूचना पर विचार किया गया है, वह केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती विश्लेषण में मूल्यांकित क्षति के प्रमुख आर्थिक मानदंडों ने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में पर्याप्त सुधार दर्शाया है।

भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए ग्राहकों को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

क्षति मार्जिन की मात्रा

80. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के पहुँच मूल्य की तुलना की है। क्षति मार्जिन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है:

क्षति मार्जिन

विवरण	यूनिट	डीजीसीआईएस आयात आंकड़ों पर आधारित
पहुँच मूल्य	रुपए प्रति दर्जन	***
एनआईपी	रुपए प्रति दर्जन	***
क्षति मार्जिन	रुपए प्रति दर्जन	***
	अमेरिकी डॉलर प्रति दर्जन	***
	%	***
	% रेंज	360-370

81. निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का स्तर काफी है।

झ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

82. प्रकटन पश्चात स्तर पर उठाए गए मुद्दों को जांच के दौरान पूर्व में पहले ही उठाया गया है और उनका उपयुक्त रूप से समाधान भी कर दिया गया है। तथापि, स्पष्टता के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध संक्षेप में नीचे दिए गए हैं तथा निम्नलिखित रूप में उनका पुनः समाधान किया गया है:

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

83. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियां संक्षेप में निम्नलिखित रूप में हैं:

- i. याचिकाकर्ताओं द्वारा आयात एवं विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद तुलनीय एवं समान वस्तु हैं।
- ii. वर्तमान मामले में पीसीएन बनाने से कोई उद्देश्य वर्तमान मामले में निर्यातकों का कोई सहयोग न होने के कारण पूरा नहीं होता, प्राधिकारी के लिए पीसीएन वर्गीकरण आधार पर आंकड़ों की तुलना करना संभव नहीं था।
- iii. आयात आंकड़े पृथक्करण के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करते।
- iv. याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए अनुसार पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन का भारित औसत निर्धारण दी गई स्थिति में सर्वोत्तम कार्रवाई है।
- v. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आधार की सही-सही जांच की है। असंगठित और बिखरे क्षेत्र के मामले में प्राधिकारी ने हमेशा घरेलू उद्योग के आधार की जांच विश्वसनीय सूचना के आधार पर की है।
- vi. प्रकटन विवरण में पाटन मार्जिन काफी है। यदि प्राधिकारी परिवर्तन करते हैं अथवा जांच पुनः करते हैं तो घरेलू उद्योग को उसका समुचित रूप से समाधान करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए।
- vii. प्राधिकारी यह जांच नहीं कर पाए कि मांग 22 प्रतिशत बढ़ी, परंतु घरेलू उद्योग की बिक्री केवल 13 प्रतिशत तक बढ़ी। वस्तुतः अन्य उत्पादकों की बिक्री समर्थकों को छोड़कर 17 प्रतिशत तक कम हुई है।
- viii. प्राधिकारी को यह लिखने की आवश्यकता है कि आयात उत्पादन एवं खपत की तुलना में तथा पूर्ण रूप से बढ़े हैं जो यह स्पष्ट दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को स्थानीय विनिर्माताओं और आपूर्ति के जोखिम पर लेता है।
- ix. प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि कोई न्यूनीकरण/हास नहीं है, आधारहीन है।
- x. प्रकटन विवरण में क्षमता उपयोग की दर दी गई है जो कि एक सामान्य परिपाटी नहीं है। वास्तविक आंकड़ों में क्षमता उपयोग जांच की अवधि में कम हुआ है और 40-50 प्रतिशत क्षमता अनुपयुक्त रहती है।
- xi. 25 प्रतिशत मांग चीनी आयातों ले ली गई है। याचिकाकर्ता को लाभप्रद स्तर पर कीमत रखने के कारण मात्रात्मक क्षति हो रही है।
- xii. प्राधिकारी ने यह गलत माना है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में काफी लाभ अर्जित किया। अतः लाभप्रदता और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क नहीं हो सकता। घरेलू उद्योग ने 1-2 रुपए प्रति दर्जन का लाभ अर्जित किया जहां उत्पाद की कुल लागत 175-180 रुपए प्रति दर्जन है।
- xiii. प्राधिकारी को आर्थिक मानदंडों की वास्तविक एवं संभावित स्थितियों की जांच करने की आवश्यकता है।
- xiv. 1-2 रुपए प्रति दर्जन लाभ कारणात्मक संपर्क को कम नहीं कर सकता।
- xv. घरेलू उद्योग यह समझने में विफल है कि प्राधिकारी ने 7-10 प्रतिशत आरओसीई को "पर्याप्त" कैसे कहा। प्राधिकारी 22 प्रतिशत आरओसीई से सहमत होने की अपनी सतत परिपाटी से सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं।
- xvi. घरेलू उद्योग एक पूंजी गहन क्षेत्र नहीं है और इसीलिए यहां तक कि मानक 22 प्रतिशत आरओसीई उनके द्वारा अर्जित 7-10 प्रतिशत को छोड़कर उनके बने रहने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- xvii. अत्यधिक पाटन के कारण मालसूची बढ़ी है।
- xviii. प्राधिकारी ने सामान्य परिपाटी के विरुद्ध बाजार हिस्से की दर दी है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मांग में वृद्धि के बावजूद गिरावट आई है।

निर्यातकों/उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

84. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

- i. लागत एवं कीमत की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के प्लेइंग कार्डों को एक उत्पाद नहीं माना जा सकता। हितबद्ध पक्षकारों को पीसीएन के संबंध में सूचना दायर नहीं करनी है।
- ii. याचिकाकर्ताओं को याचिका दायर करते समय प्राधिकारी के समक्ष समस्त सूचना लानी चाहिए थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपना गया दृष्टिकोण सूचना प्रदान न करने में दुर्भावपूर्ण था और अब संगत मानदंड का सुझाव न देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों पर दोष डाल रहे हैं।
- iii. पीसीएन संबंधी सूचना याचिकाकर्ताओं से हमेशा पहले आती है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास ही केवल आयातों के संबंध में ही संगत सूचना नहीं होती अपितु उनके अपने आंकड़ों के संबंध में भी संगत सूचना होती है।
- iv. यह तथ्य कि आयात आंकड़ों में निहित विवरण पूर्णतः संगत है, याचिकाकर्ता पीसीएन का सुझाव देने के लिए कोई दृष्टिकोण का सुझाव अपना सकते थे और उसके बाद पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन निर्धारित कर सकते थे।
- v. यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि वे भिन्न-भिन्न उत्पाद किस्मों की कीमत असंगत रूप से निर्धारित करते रहे हैं और उनके द्वारा लगाई गई कीमतों में अंतर का कोई मानक मानदंड नहीं है तथा याचिकाकर्ता उपभोक्ताओं को बढ़ाते रहे हैं।
- vi. वर्तमान में, याचिकाकर्ताओं ने पीसीएन सिद्धांत का भी सुझाव नहीं दिया है और उसकी बजाए ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है कि उत्पाद को विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों में वर्गीकृत करने के लिए कोई मानक मानदंड उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट रूप से अमान्य है।
- vii. वर्तमान जांच नियम 6(8) का सहारा लेने की बजाए रद्द किए जाने की आवश्यकता है। यदि याचिकाकर्ता खुद सहमत हैं कि कोई मानदंड नहीं है तो इसका मतलब यह है कि प्राधिकारी वर्तमान मामले में उपयुक्त निर्धारण नहीं कर सकते।
- viii. हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत के तुरंत बाद प्राधिकारी को लिखा था, जिसमें याचिकाकर्ताओं की कीमत सूची संलग्न की गई थी और याचिकाकर्ताओं की कीमत दर का विश्लेषण किया गया था, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के निरीक्षण के लिए उन पत्रों को सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा था।
- ix. आयात आंकड़ों की ध्यानपूर्वक जांच करने पर यह देखा जा सकता है कि कई पंक्तियों में उत्पाद के विवरण में उल्लिखित मद “कागज से बनाए गए प्लेइंग कार्ड”, “100 प्रतिशत प्लास्टिक प्लेइंग कार्ड”, “कम गुणवत्ता के कागज के प्लेइंग कार्ड” हैं। आपके संदर्भ के लिए आयात सूची (टी/टी) का नमूना अनुरोध के साथ संलग्न है। याचिकाकर्ताओं ने उसे विभिन्न किस्मों में अलग-अलग करने के लिए आयात आंकड़ों का विश्लेषण करने में कोई प्रयास नहीं किए।
- x. सूचना की परिशुद्धता और पर्याप्तता के आधार पर वर्तमान जांच को रद्द किए जाने की आवश्यकता है।
- xi. आयातित उत्पाद कम गुणवत्ता के कागज और रिसाइकिल कागज से बनाए जाते हैं। यह उपभोक्ताओं के कई क्षेत्रों तक जाता है जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद उच्च गुणवत्ता के कागज के हैं अथवा प्लास्टिक प्लेइंग कार्ड हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद का काफी अनुपात प्लास्टिक का है।
- xii. प्रथम दृष्टया यह देखा जा सकता है कि याचिका मुंबई आधारित विनिर्माताओं द्वारा दायर की गई है। यहां तक कि भारतीय प्लेइंग कार्ड एसोसिएशन के सदस्य मुंबई आधारित हैं। याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र में दिल्ली आधारित विनिर्माताओं को शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया है।
- xiii. इतने अधिक पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत कटौती से आयात चिंताजनक दर पर नहीं बढ़े हैं।
- xiv. घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच दी गई इस प्रकार की कीमत के अंतर से याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में कैसे समर्थ थे।
- xv. घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच 300 प्रतिशत से अधिक के कीमत अंतर के बावजूद यह आश्चर्यजनक है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन और घरेलू बिक्री में सुधार हुआ और याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे पाटित आयातों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
- xvi. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समान वस्तुओं की तुलना नहीं की जा रही है। आयात घरेलू कार्डों की तुलना में प्लेइंग कार्ड्स की विभिन्न श्रेणी/किस्मों के हैं। ये दोनों दो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में बेचे जा रहे हैं। ये दोनों एक-दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर रहे हैं।

- xvii. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को हो रही तथाकथित क्षति का विश्लेषण किया था। हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के सभी क्षति मानदंडों की तुलना जांच की अवधि के सभी वर्षों से की।
- xviii. संबद्ध आयातों, अन्य देशों से आयातों के अलावा याचिकाकर्ताओं और अन्य उत्पादकों की बिक्री भी काफी बढ़ी है।
- xix. मांग आंकड़ों में केवल मुंबई आधारित उत्पादकों की बिक्री शामिल है और उसमें दिल्ली आधारित उत्पादकों और भारत के अन्य भागों के उत्पादकों की बिक्री शामिल नहीं है। यदि अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री शामिल की जाती है तो यह देखा जाएगा कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य भारतीय उत्पादकों में अपना बाजार हिस्सा खोया है।
- xx. प्रत्येक याचिकाकर्ता कंपनी का उत्पादन बढ़ा है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पूरी क्षति की अवधि में स्थिर रहा है।
- xxi. उत्पादन क्षति की अवधि में बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, क्षमता उपयोग में परिवर्तन इतना कम है कि वह क्षति की अवधि में उसी दर के अंतर्गत गिर गया है। इस प्रकार, सूचीबद्ध क्षमता उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- xxii. याचिकाकर्ताओं द्वारा भारी अनुपयुक्त क्षमताओं के बावजूद क्षमता बढ़ाई गई थी।
- xxiii. निर्धारित कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री सही तुलना पर आधारित नहीं है और इसीलिए वह शुल्क लगाए जाने का आधार नहीं हो सकती।
- xxiv. प्राधिकारी ने सही-सही माना है कि लाभप्रदता प्रभावित नहीं हुई है, याचिकाकर्ताओं को 2013-14 के दौरान हानियां हो रही थीं, परंतु उसके बाद जांच की अवधि के दौरान उन्हें काफी लाभ हुआ।
- xxv. बिक्री, उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग इन सभी प्रवृत्तियों में पूरी क्षति की अवधि में सुधार दर्शाया है। केवल याचिकाकर्ताओं की बिक्री ही नहीं बल्कि समर्थकों और अन्य उत्पादकों की बिक्री भी बढ़ी है।
- xxvi. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की आरओसीई, आरओआई और लाभप्रदता में भारी वृद्धि हुई है।
- xxvii. बाजार हिस्से में परिवर्तन इतना कम है कि वह क्षति की अवधि में समान दर पर रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को बाजार हिस्से के कारण क्षति नहीं हुई है।
- xxviii. याचिकाकर्ताओं की मालसूची बढ़ी है। यह फिर भी बढ़ते हुए उत्पादन और उत्पादों की व्यापक शृंखला के कारण है जिसे किसी भी आपूर्तिकर्ता को बाजार में पेश करना चाहिए।
- xxix. मांग एवं आपूर्ति का अंतराल भारी है।
- xxx. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्द्धात्मकता जैसे अन्य कारकों की भी जांच करें। विभिन्न विनिर्माताओं की कीमत सूची यह दर्शाती है कि (क) ये विनिर्माता एक-दूसरे के साथ भयानक रूप से प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं, (ख) घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच कीमत का अंतर इतना अधिक है कि घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं हो सकती, (ग) आयातित उत्पाद दिल्ली आधारित उत्पादकों जैसे छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे उत्पादों से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

85. यह नोट किया जाता है कि प्रकटन पश्चात स्तर पर उठाए गए मुद्दों की जांच प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त संगत पैराग्राफों में पहली ही कर दी गई है।

86. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्राधिकारी को आर्थिक मानदंडों से संबंधित वास्तविक एवं संभावित स्थितियों की जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग और आर्थिक मानदंडों में क्षति से संबंधित संभावित स्थितियों के संबंध में कोई दावा नहीं किया है। जब याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के संभावित प्रभाव के कारण क्षति का दावा नहीं किया है तो प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के संभावित प्रभावों की जांच नहीं कर सकते।

उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ब. निष्कर्ष

87. निष्कर्ष संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा क्षति की अवधि में पूर्ण रूप में तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के अनुपात में बढ़ी है। पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं और काफी अधिक हैं। तथापि, पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन की इतनी अधिक मात्रा के बावजूद

- घरेलू उद्योग अपनी क्षमता और अपना उत्पादन बढ़ाने में सक्षम रहा है। इसके अतिरिक्त, क्षति की अवधि में बिक्री में सुधार आया।
- ii. यद्यपि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई, तथापि यह नोट किया जाता है कि समर्थक उत्पादकों का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा।
 - iii. यहां तक कि जब मालसूची का स्तर बढ़ा, तो घरेलू उद्योग ने मालसूची का पूर्ण स्तर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचे गए प्लेइंग कार्डों की उत्पादन दर और व्यापक श्रृंखला को देखते हुए इतना अधिक नहीं था।
 - iv. इतने अधिक पाटन मार्जिन और कीमत कटौती के बावजूद, आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं हुआ और घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय में सुधार लाने में सक्षम था।
 - v. यह मानते हुए कि घरेलू उद्योग को भारी कीमत कटौती के परिणामस्वरूप न्यूनीकरण अथवा ह्रास के प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा, उत्पाद के पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक नहीं थे।
 - vi. अतः घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पाटित आयातों का परिणामी प्रभाव नहीं था। निष्कर्ष स्वरूप यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

ट. सिफारिश

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्कों के संबंध में सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्कों की जांच की शुरूआत की गई थी तथा जांच की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर दिए गए कारणों से घरेलू उद्योग को पाटित आयातों और वास्तविक क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है। अतः नियम 14(ख), (ड) और नियम 11(2) के साथ पठित नियम 17(1)(iii) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (v) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी वर्तमान जांच, जो 30 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/43/2016-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी, को रद्द करने का निर्णय लेते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2018

(Final Finding)

Sub: Anti-dumping investigation concerning imports of “Playing Cards” originating in or exported from China PR.

F. No. 14/43/2016-DGAD.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules) thereof, M/s. Parksons Graphics Private Limited, M/s. Parksons Cartamundi Private Limited and M/s. T M Printers Private Limited (hereinafter referred to as the “applicants” or “petitioners” or “domestic industry”) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the AD Rules, for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “**Playing Cards**” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR. (hereinafter also referred to as the subject country), and requested for initiation of an investigation for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2. The Authority on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant issued a public notice dated 30th March 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in accordance with Rule 6(1) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. Procedure

3. The procedure described below has been followed:
 - a. The Authority notified the Embassy of China PR in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.
 - b. The Authority sent copy of initiation notification to the Embassy of China PR in India, known producers/ exporters from the subject country and known importers/ users/ associations of the subject goods as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
 - c. The Authority forwarded copy of the non-confidential version of the application to the Embassy of China PR in India, known producers/exporters from the subject country and known importers of the subject goods, in accordance with the AD Rules. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.
 - d. The Embassy of China PR in India was also requested to advise the producers/exporters from their country to file their responses within the prescribed time limits.
 - e. The Authority sent the exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

China PR

1. Wengzhou Tiange Printing Co. Ltd.
2. Shenzhen Wangjing Printing Co., Ltd.
3. Nanjing Bewe Intl Trading Co., Ltd
4. Heke Packing and Printing Plant Co. Ltd
5. Shanghai King Show Industrial Co., Ltd.
6. Guangzhou Jinguan Printing Co., Ltd.
7. Wuyi Dadi Printing Co., Ltd.
8. Dongguan Fusheng Printing Co., Ltd.
9. Yuyao Feifan Leisure & Entertainment Goods Co., Ltd.
10. Dongguan Dong Hong Presswork Limited
- f. None of the exporter/producer from the subject country has responded to the Authority in the present investigation.
- g. Questionnaires were sent to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 1. Western Greenville Company
 2. Prakash Trading Company
 3. Myriad Holdings
 4. Miles Retail
 5. Poker Stuff India
 6. Adishwar Impex Pvt. Ltd.

- h. None of the importers/user of the subject goods has filed questionnaire response. However, the following importers have filed submissions/comments during the course of investigation:
 - 1. Zen Impex
 - 2. Velocity
 - 3. Sun Seas Trading Company
 - 4. Metro card & Print Private Limited
 - 5. San International,
 - 6. Jainico Traders,
 - 7. A J Impex,
- i. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in the present disclosure statement.
- j. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- k. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.
- l. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- m. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules. It has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- n. Verification of the information provided by the applicant domestic industry was carried out by the Authority to the extent deemed necessary and only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- o. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2015 to 30th September 2016 (18 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the POI.
- p. The petitioners had submitted the petition alleging dumping of the subject goods from the subject country relying upon transaction wise imports data sourced from IBIS. However, request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods. The Authority has relied upon the transaction-wise DGCI&S import data.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 30th January, 2018. All the parties attending the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to submit their rejoinders by 12th February, 2018.
- r. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the

present investigation, have been appropriately considered by the Authority.

- s. A Disclosure Statement was issued on 20.02.2018 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 26.02.2018 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- t. Exchange rate for conversion of US\$ to INR is considered for the POI as INR 66.53 as per customs data.
- u. In this notification, *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

B. Product under Consideration and Like Article

- 4. The submissions have been filed by DI and importers regarding the scope of PUC are summarized as below:

Submissions made by the Domestic Industry

- 5. Submissions made by the Domestic Industry are as follows:
 - a. The product under consideration (PUC) in the present investigation is “*Playing Cards*”. Playing cards are a pack of 52 rectangular thin cards made of paper or PVC, generally used for playing a variety of games. Playing cards have a sequence of numbers and symbols such as diamonds, hearts, clubs, or spades on the face, but an identical design on the reverse. A complete set of 52 playing cards may be called a pack or a deck or a set.
 - b. The PUC is used in playing various games of chance and skill. They are also used for illusions, cardistry, building card structures, cartomancy and memory sport.
 - c. The PUC is classified under tariff item 9504 40 00 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the imports have also been observed in certain other ITC HS Codes viz. 3923 90 90, 3926 10 19, 3926 40 49, 3926 90 99, 4818 90 00, 4821 90 90, 4901 10 10, 4901 10 90, 8523 21 00, 9403 89 00, 9404 90 99, 9503 00 30, 9503 00 90, 9504 90 10, 9504 90 90, 9505 90 90, 9506 91 90, 9506 99 90 and 98049000. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
 - d. Zen Impex, Velocity and Sun Seas Trading, Metro Cards and Printers, San International, Jainico traders and AJ Impax have not filed the questionnaire response. Further, they have not suggested any parameter / criterion for classification of PUC into different categories / grades. The interested parties have made their submission only to derail the investigation.
 - e. There are no standard parameters / criteria available to classify the Playing Cards into different categories / grades. Even the product description given in the import statistics also does not provide any reasonable parameter / criterion to classify the PUC into different categories / grades. This has affected the category wise / grade wise comparison of landed value with domestic selling price and non injurious price of the Domestic Industry.

Submissions made by other interested parties

- 6. Submissions made by the other interested parties are as follows:
 - a. The petition defines PUC as Playing cards- as one product. Nothing is more misleading than that. The product under consideration has wide varieties and all types of playing cards cannot be treated as one. Analysis of price list of the supporters and petitioners show that there are at least 62 types of price for playing cards. Also the price range between the minimum to maximum price of cards are upto 1983%. Logically there cannot be so many types of price for one type of playing cards.
 - b. Petitioners have sought to underplay the fact that there are numerous kinds of products within the definition of product under consideration. The petitioners must explain reasons for holding so many different prices if the product is only two types. Evidently, the product is not of two types. The product is of several types.
 - c. The petitioners sought to justify non identification of PCN by stating that the same would have served no useful purpose, had the petitioners identified a PCN. In other words, the petitioners agree that the quality and quantity of import information available was not sufficient to identify the import types involved.

- d. If that is the case, the authority will have to conclude existence of insufficient evidence and not application of principles of best available information. WTO Appellate body report of Guatemala Cement II and Bed linen is referred and relied upon where it was held that the Authority is required to examine adequacy and accuracy of the evidences as well as the sufficiency of the evidences before initiating the investigation and sufficiency of evidences is required to justify the initiation of investigation. Based on the accuracy and adequacy of the information the present investigations need to be terminated
- e. There are investigations like Aluminium foil, Elastomeric yarn, Radiators, Alloy wheels, nonwoven fabric, Electrical insulators where the authority directed the domestic industry to form PCN and issued clarification the scope of product under consideration and also sought comments of the interested parties after that.
- f. In the present case petitioners had sufficient time to form PCN, despite having so many qualities and types of the product under consideration the petitioners failed to form PCN and there is no apple to apple comparison.
- g. The petitioners failed to segregate the import data properly. Several item which is non PUC but are marked as PUC in the import data filed by the them. Items like children playing cards, games, playing cards toys, cardboard children playing game, game poker box etc. have been treated as PUC.
- h. Imports are coming under various unit of measurements such as Boxes, Dozens, Grams, Kgs, numbers, packets, set, unit etc. the petitioners have taken the unit of measurement as dozen. It is nowhere explained in the petition the methodology for converting other unit of measurements into dozen.

Examination by the Authority

7. The product under consideration (PUC) in the present investigation is “*Playing Cards*”.
8. Playing cards are a pack of 52 rectangular thin cards made of paper or PVC, generally used for playing a variety of games. Playing cards have a sequence of numbers and symbols such as diamonds, hearts, clubs, or spades on the face, but an identical design on the reverse. A complete set of 52 playing cards may be called a pack or a deck or a set. The PUC is used in playing various games of chance and skill. They are also used for illusions, cardistry, building card structures, cartomancy and memory sport.
9. The PUC is classified under tariff item 9504 40 00 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the imports have also been observed in certain other ITC HS Codes viz. 3923 90 90, 3926 10 19, 3926 40 49, 3926 90 99, 4818 90 00, 4821 90 90, 4901 10 10, 4901 10 90, 8523 21 00, 9403 89 00, 9404 90 99, 9503 00 30, 9503 00 90, 9504 90 10, 9504 90 90, 9505 90 90, 9506 91 90, 9506 99 90 and 98049000. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
10. With regard to the issue of significant price difference in different types of playing cards as appearing in the pricelist issued by the petitioners, Authority notes that neither domestic industry nor importers have suggested any parameter / criterion for classification of PUC into different categories / grades.
11. There are no standard parameters / criteria available to classify the Playing Cards into different categories / grades. Even the product description given in the import statistics does not provide any reasonable parameter / criterion to classify the PUC into different categories / grades.
12. Interested parties contended that the petitioner has combined all the types of products into one category. Hence, there is no proper comparison of products done. In other words there was no apple to apple comparison. Had there been proper comparison, such huge dumping margin and price undercutting was not possible.
13. The Authority notes that it is undisputed that the product is produced in a number of different product types and which could be categorized further. The parameters for product classification proposed by interested parties were not disputed by the Domestic Industry. The Domestic Industry instead contended that the same is unnecessary. Since there is no information on record with regard to separate costs and price of different types of product involved, the Authority is constrained to determine dumping margin on the basis of weighted averages of the import price.

D. Domestic Industry and Standing**Submissions made by the Domestic Industry**

14. Submissions made by the Domestic Industry are as follows:

- a. The Petitioners share in total Indian production of product under consideration is 59% during the proposed POI. Further, the share of Petitioners along with supporters is 91% of the total Indian production of Playing Cards. Accordingly, the petitioners clearly satisfy the requirement of standing and thus constitute 'domestic industry' in India for the product concerned in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the AD Rules and that they are fully competent to bring this petition for imposition of anti-dumping duty on subject goods.

Submissions made by other interested parties

15. Submissions made by the other interested parties are as follows:

- a. The petition has been filed on behalf of the Indian Playing Cards Manufacturers' Association Limited which has 23 members, out of that 3 members are the petitioners and 7 of the other members have supported the petition. The petitioners have cherry picked the domestic industry.
- b. There are various manufacturers of the product concerned in other parts of India who are not members of this association. There are almost 50-80 producers of the playing cards in Delhi, none of them are part of the petition. The petitioners do not have the adequate standing as "major proportion" of the total India production without adding these manufacturers.
- c. No efforts were made by the petitioners to get information about the other manufacturers of the subject goods. The petition has been filed on the basis of best available information with the industry.
- d. The authority never had an occasion to consider all the manufacturers of the subject goods at the stage of initiation. Thus the authority did not have complete data with regard to Indian production at the stage of initiation, the entire investigation is required to be terminated holding that the information at the time of initiation with regard to standing was not only excessively incomplete, but also excessively false and excessively misleading.
- e. Rule 5 of the AD Rules imposes some obligation of the DA at the time of initiation with regard to definition of product under consideration, standing and scope of domestic industry, evidence of dumping, evidence of injury, evidence of causal link. While a prima-facie satisfaction may be sufficient with regard to essential parameters such as evidence of dumping, evidence of injury, evidence of causal link, final determination is required to be made with regard to standing aspect.
- f. Since the authority is required to determine that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and no investigation shall be initiated unless the threshold laid down under the Rules is met and the application shall be deemed to have been made if the threshold under the law is met, it is evident that a determination is required to be made by the authority at the stage of initiation and such determination attains finality upon initiation. If it is subsequently found that the information in the petition was grossly incomplete, insufficient, false & misleading, the standing made at the time of initiation is vitiated, flawed and bad in law. The investigation is needed to be terminated on this ground itself.
- g. Several High Court orders have held that standing is required to be finally determined at the stage of initiation and is not open to the determination at the stage of findings. Even otherwise, the petitioners candidly and rightly accepted at the time of hearing that the information was provided on the basis of knowledge and belief. The petitioners presumed that they form the major proportion of the domestic industry without including the other producers of the subject goods.
- h. The petitioners have sought justification of their standing on the basis of the information of The Indian Playing Cards Manufacturer's Association Limited. To quite surprise to the interested parties there is no website of the Association and there are no details about the members of the Association. This creates a serious doubt on the credentials of the Association and its members.
- i. None of the member of the Association is Delhi-based, despite the fact that Delhi has a large number of Playing cards manufactures.

Examination of the Authority

16. Rule 2 (b) of the AD rules defines the domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

17. The application has been filed M/s Parksons Graphics Private Limited, M/s Parksons Cartamundi Private Limited and M/s T M Printers Private Limited. The Petition is also supported by the followings:

- 1) JMK Enterprises
- 2) Kagalwala Packaging Private Limited
- 3) LKM Enterprises
- 4) Nandi Printers Private Limited
- 5) Ajanta Print Arts
- 6) Bathija Enterprises
- 7) T.M. Enterprises Private Limited (Formerly T M Enterprises)

18. The petitioners have claimed that they command (55% to 59 %) of Indian production, as per data made available in Injury period. The interested parties disputed the claim of the petitioner and contended that there are 75-80 producers of the PUC. The interested parties also contended that there are large number of producers of the PUC, details of which is completely suppressed by the petitioners. Post issuance of the disclosure statement, M/s Delhi Playing Cards Association, bearing address 5740, 1st Floor, Gandhi Market, Sadar Bazar, Delhi has written to the Authority stating that the number of producers used to be in the region of 10-14 earlier in the past, but, owing to unyielding imports, most of the producers had to shutdown. However, no verifiable information, nor names of producers in the past, or producers who have closed down production due to imports has been provided by this Association. Even name of the producers of the product have not been mentioned by this Association in its letter.

19. The Authority notes that the association has provided no information either with regard to its existence, or details of the producers in North who are its members or details of the producers in North who are manufacturers of playing cards. The Authority has found no details either, with regard to its existence of being a registered/recognized body.

20. The petitioner contended that many manufacturers of playing cards have now become importers of the PUC and submitted that M/s Metro Cards and Prints was earlier manufacturing playing cards and now has become importer. However, barring name of M/s Metro Cards and Prints, no other producer has been identified by the petitioner who has become importer now. M/s Metro Cards and Printers submitted a letter stating that the company had stopped production in 2006, i.e. more than a decade back. The company has also stated that the plant was shut down due to reasons other than dumped imports (due to inability of the management to continue to handle manufacturing operations with increase age and family members pursuing different career). In particular, the company submitted that the dumping of the product was not the reason for shutting down production and in fact, there were hardly any imports of the product when the company had shutdown the production.

21. The Authority notes arguments of various interested parties and holds that the Authority has determined standing on the basis of information on record.

22. The petitioners accounts for a major proportion of the total domestic production of the product under consideration.

C. Confidentiality**Submissions made by the Domestic Industry**

23. Submissions made by the domestic industry are as follows

- a. All requirements under Rule 7 are fulfilled and there is no instance pointed out when the Petitioner has not provided data where it was not entitled to.
- b. Confidentiality claimed is as per the practice permitted by the Designated Authority. Costing information Needs confidentiality as it constitutes highly business proprietary information of the petitioner.
- c. The interested parties have not submitted the importers questionnaires even.

Submissions made by other interested parties

24. There are no submissions made by the other interested parties on confidentiality claims.

Examination of the Authority

25. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule(2),(3)(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

D. Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Dumping Margin**NORMAL VALUE**

27. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

- b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Submissions made by other interested parties

28. Submissions made by the other interested parties are as follows:

- a. The interested parties have submitted that in view of significant price difference in different types of playing cards as appearing in the pricelist issued by the petitioners and other domestic producers for the product under consideration, determination of the single dumping margin, price undercutting and injury margin is inappropriate.

Examination by the Authority

29. It is noted that none of the producer/exporter of subject goods in China PR has responded to the Authority in the present investigation. Therefore, the Authority determined normal value as per facts available in terms of section 9A(6A) and Rule 6(8) of the AD Rules.

Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

30. In the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in subject country and any other market economy third country, the Designated Authority has constructed the normal value for China PR on the basis of best available information for the like product, with a reasonable profit margin. Accordingly, the Normal Value for all the producer/exporters of the subject goods from China PR has been constructed and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

E. EXPORT PRICE

31. The Authority notes that none of the producer/exporter from China PR has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in China PR, the Authority has determined the weighted average export price for subject goods on the basis of facts available and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

DUMPING MARGIN

32. The export price to India has been compared with the normal value to determine the dumping margin. The dumping margin during the POI for all the exporters/producers from the subject country has been determined as shown in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin Table

Particulars	Unit	Based on DGCIS Import Data
Normal Value	USD per Doz.	***
Ex-factory export price	USD per Doz.	***
Dumping Margin	USD per Doz.	***
	%	***
	Range	330-340

33. It is seen that the dumping margins are quite significant and more than the de-minimis limits prescribed under the Rules in respect of the exports made by all the producers-exporters of the product under consideration from the subject country.

F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

34. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
35. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules.

Views of the domestic industry

36. The following are the submissions with regard to injury related issues made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:
 - a. Imports of the subject goods have increased in absolute terms over the entire period of investigation. Imports of the PUC from the subject country have increased in absolute terms.
 - b. Imports of the subject goods have increased relative to production and also relative to consumption in India.
 - c. Market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand and the market share of imports from subject country sharply increased from 2012-13 to POI (A).
 - d. The Domestic Industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand.
 - e. Inventories of the Domestic Industry have been on the rise as the Domestic Industry has not been able to increase its sales despite increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.
 - f. There is significant price undercutting and price underselling due to low priced dumped imports coming into India.
 - g. The Domestic Industry's profitability and return on capital employed have been drastically affected. The profitability has been negative throughout the injury investigation period because throughout the injury investigation period, imports have been coming at very low prices.
 - h. Performance of the Domestic Industry was quite adverse in terms of profits, return on investments and cash flow. The Domestic Industry is not able to realize non injurious price for the product.
 - i. The analysis overwhelmingly indicates that the Domestic Industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of PUC into India. There exists a strong nexus between the increase in dumped imports of the subject goods and the material injury being suffered by the Domestic Industry.

Views of importers and other Interested Parties regarding the injury claims of domestic industry

37. Submissions made by the other interested parties are as follows:
 - a. There are various grades of product under consideration and in order to ensure fair comparison, the petitioners should have done type wise comparison. The petitioners' brochure itself shows various types of product with huge price range. Therefore, price undercutting on aggregated basis is misleading and cannot be formed as a basis for determination of injury to the domestic industry.

- b. With different types of product concern, any aggregate comparison is misleading. Assuming not admitting, that the landed price of imports is lower than the cost domestic industry, the domestic industry is able to increase its profitability.
- c. It is interesting to see that selling price of the domestic industry has increased more than the cost of sales. In fact the cost of sales remains unchanged in the Period of investigation and the selling price has increased by significantly. Thereby showing that the imports have not caused any suppression or depression to the prices of the domestic industry
- d. Such huge dumping margin calculated by the petitioners is highly misleading. There are different grades of the product under consideration and there should be grade-wise comparison. The petitioners have compared the lowest price of imports with their highest quality product. Also, the petitioners have arrived at wrong import price calculation.
- e. Evidently, in the facts of present case, the information available in the application was not sufficient to come to even a prima facie conclusion with regard to the import price.
- f. In a situation where import data is insufficient to adequately establish the export price, the authority should rely upon other publicly available information and evidences such as resale price of the product. Such resale price of the product can readily be established by considering the price list of imported product resold by the importers.
- g. Existence of a variety of products further establishes inappropriateness of weighted average analysis that the petitioners contend is sufficient to determine the export price. Evidently, the petitioners grossly misled the authority in believing that there was lack of available information for determining import price.
- h. Considering the fact that import prices are woefully inadequate to determine grade wise prices, minimum that the petitioners is required to do is to determine export price on alternate basis.
- i. Export price definition will show that if the import price appears unreliable for any reason including the existence of different product types which cannot be identified in the import data, the authority is required to consider alternate means.
- j. Petitioners had a malafide intention in not presenting grade wise analysis at the stage of petition. It would be relevant to refer to the anti-dumping investigation concerning imports of hot and cold rolled carbon steel wherein the petitioners had identified a PCN methodology in the application; but, ignored the same for the purpose of determination of dumping margin and injury margin. At the stage of final finding also, the authority was constrained in ignoring the PCN proposed by the petitioners at the stage of petition!
- k. It is, thus, evident that the petitioners in the present case has also adopted similar strategy of (a) not identifying the PCN, (b) seeking initiation (c) waiting for interested parties to raise the issue and (d) thereafter contend that the exporters have not cooperated! The fact that exporters have not cooperated does not mean anything with regard to the need for identification of PCN. Exporters also could not cooperate only because this anomaly that the petitioners has allowed to peep into this case.
- l. The authority should prevent the petitioners from adopting a strategy/tactics similar to steel case wherein despite identification of a PCN by the petitioners itself, the Designated Authority was constrained to ignore the same at the stage of determination even when the interested parties had cooperated in that investigation.
- m. In a situation where authority comes to a conclusion that there was inadequate information/evidence in the petition, the principles of best available information cannot be invoked at the stage of petition and it must instead be concluded that the petition lacked sufficient evidence to justify initiation.
- n. The petitioners seems to have projected to the authority that in case of injury/losses it follows that it will include evaluation of all economic factors and indices to have bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in all the volume and price parameters of the domestic industry and it is not necessary to independently establish injury. It is however evident

that the placement of word “and” between the dumped imports and injury that both the conditions must exist at the same time and mere establishment of either of these is insufficient before the authority can conclude that dumped imports of the product are causing injury to the domestic injury.

- o. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the authority is required to consider whether any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. In the facts of the present case, however, this condition is completely absent.
- p. The petitioners are required to consider the performance of the domestic industry in POI and establish whether the same shows that the performance of the domestic industry in the POI was “injurious”, having regard to performance over the preceding years.
- q. Performance of the domestic industry by considering – (a) performance of domestic industry in POI with reference to base year, (b) performance of domestic industry in POI with reference to next to base year (subsequent year) and (c) performance of domestic industry in POI with reference to previous year (just preceding year) .Regardless of whether performance of the domestic industry in the present POI is compared with base year, subsequent year or just preceding year, performance of the domestic industry does not show any deterioration.
- r. Trend from base year to POI, previous year to POI and subsequent year to the POI, with regard to production, sales, capacity utilization, stocks and capacities don’t show any deterioration.
- s. Trends with regard to profit, cash profit and ROI of the domestic industry does not show any deterioration whether compared with base year to POI, previous year to POI or subsequent year to the Period of investigation.
- t. Regardless of the period for which performance is compared, there is no deterioration in performance of the domestic industry barring except (a) capacity utilization, (b) market share and (c) inventory. These parameters are however addressed below and it would be seen that the domestic industry cannot claim injury even on these accounts.
- u. Trends in capacity, capacity utilization and demand. It would be seen that the domestic industry has reported increase in capacity. This increase in capacities is despite existing capacities remaining grossly unutilized. Thus, when existing capacities were so grossly unutilized, the domestic industry had no justification for enhancement of capacities. But, the domestic industry did the same.
- v. The decline in capacity utilization is despite increase in production and therefore is a result of increase in capacities. If capacity is enhanced, its adverse effect will naturally fall on capacity utilization, particularly when existing capacities were grossly underutilized.
- w. Increase in capacity is due to one of the petitioners has added capacity. There is a slight decline in the capacity utilization because the petitioners added capacities despite having underutilized existing capacities.
- x. The Petitioners claims decline in market share as a parameter of injury. there is no way domestic industry can claim that they have lost market share so materially that this per se should be sufficient to hold “material injury”, when the above is trend in decline in market share. A mere 2% decline in market share is grossly insufficient and could even be a result of how far imports were adequately identified.
- y. There should be a significant decline in market share in order to conclude on the basis of this parameter alone that the domestic industry has suffered injury, particularly when the entire case of domestic industry is based on this decline.
- z. Increase in inventories could be due to other new products added by the petitioners. It is not a case of increase in inventories. It is quite natural that the domestic industry is required to hold reasonable volume of inventory and for different product types in order to offer full profile of the product to the buyers. Thus, increase in inventory is not a result of dumping of the product. The

increase in inventory is a consequent impact of increase in capacities and addition of new product types.

- aa. Pattern of imports is on the basis of price bands. It would be seen that the imports have been reported in a very significant price bands. Different product types are involved which have been cumulated by the petitioners. In fact, petitioners and these imports are present in different market segment. This gets further established by a comparison of price list of petitioner's product with product supplied by other parties and Delhi based producers.
- bb. The significant difference in price list clearly shows existence of different products. The imported product from China actually competes with the product produced and supplied by Delhi based producers. It does not compete with petitioners' product. Petitioners are in fact operating on a different segment and their product is not sold in the market segment where the imported product is being sold and where the Delhi based producers are producing and selling the product.
- cc. Petitioners sought to underplay the difference in product by stating that the import description does not show the product type. Even if it is assumed that it is not possible to identify the product type in the import data, we submit that it is possible to identify the product types involved in the product produced and supplied by the petitioners and Delhi based producers. The sheer difference in the prices of Delhi based producers with the petitioners' product shows that the two are not the same
- dd. Parameters like paper or Plastic or PVC, gramage, laminated or not laminated, recycled paper or virgin paper govern the cost and price of the product and therefore should be considered for development of PCNs.
- ee. The price list of different manufacturers shows that these manufacturers are fiercely competing with each other and it is not a case where petitioners are competing with imports. In fact, the sheer price difference between the imported product and domestic industry product shows that the product produced and sold by various domestic producers is fiercely competing leading to the continued financial losses being suffered by the petitioners
- ff. The Annual report of the petitioners show that they are performing exceptionally good and same can be seen with their improving revenue, PBT,PBIT and cash profit.
- gg. Imported Chinese products are basically competing with the product manufactured by the Delhi based manufacturers' product which is a low quality paper playing cards. The playing cards made by the petitioners are high quality and cater to different segment of the market. Imported goods and petitioner's product are not like article and not even in direct competition with each other.
- hh. Import duty on playing cards, in the recent budget 2018-19 has been increased from 10 to 20%. Now since the import duty is doubled; the antidumping duty will act as a double protection for the domestic industry. Increased import duty is automatically going to result in less import and this is how the domestic industry is left with no cause and should withdraw the present investigation.
- ii. Mere increase in imports cannot be a ground for imposition of anti-dumping duty. The imports have increased due to increase in demand. However, the domestic industry has not suffered injury due to increase in imports.

Examination of the issues by the Authority

38. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:
- a. The Authority notes that landed value of imports of the subject goods from the subject country has declined.
 - b. With regard to the export performance of the domestic industry, the Authority notes that entire injury analysis is based only on the domestic performance of the petitioners.
 - c. The injury analysis has been done in the succeeding paragraphs.

Effect of Dumped Imports**Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry****Assessment of Demand**

39. The demand of subject goods has been determined by adding the domestic sales of Indian producers of like product with the imports of the subject goods from all country. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The Authority notes that demand of subject goods increased over the injury period as can be shown in the table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualized)
Imports from China PR	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	135	134	149
Imports from other countries	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	99	425	564
Domestic Sales of Petitioners	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	108	108	113
Domestic Sales of Supporters	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	112	115	126
Domestic Sales of other producers	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	91	87	83
Total demand	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	113	114	122

40. The domestic sales of petitioners, supporters and other producers of the PUC have consistently increased.

Import Volumes and Share of Subject country

41. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority has considered whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject good from the subject country has been analyzed as under:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualized)
Imports from China PR	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	135	134	149
Imports from other	Dozen	***	***	***	***

countries	Indexed	100	99	425	564
Total Imports	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	135	136	152
Total demand	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	113	114	122
Imports from China PR relative to consumption in India	%	***	***	***	***
	Range	10-20	20-30	20-30	20-30
Production of Petitioners	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	107	106	113
Imports from China PR relative to production	%	***	***	***	***
	Range	40-50	50-60	50-60	50-60

42. The Authority notes as under from the above table:

- a. Imports of subject goods from subject country have increased in absolute terms Imports from China PR in relation to domestic production have been consistently increasing and have reached a level of 58% during POI.
- b. Imports from China PR in relation to consumption and production by domestic industry have consistently increased.

Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

43. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

44. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

Price Undercutting

45. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. The domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

Particulars	Unit	April 2015 - September 2016 (POI)
Landed price of Imports	Rs. per doz.	***
Domestic Selling Price	Rs. per doz.	***
Price Undercutting	Rs. per doz.	***
	%	***
	%Range	350-360

46. The Authority notes from the aforesaid table that significant price undercutting exists. However, it is seen from table at serial no. 39 above, that despite such significant price undercutting, sales of the domestic industry have increased in absolute terms showing that domestic industry has been able to increase its sales despite such significant dumping margin and price undercutting.

Price Underselling

47. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject counties. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports.

Particulars	Unit	Based on DGCIS Import Data
Price of imports	Rs. Per Doz.	***
NIP	Rs. Per Doz.	***
Price underselling	Rs. Per Doz.	***
	%	***
	% Range	360-370

48. It is seen that the landed price of the subject goods from subject country were significantly lower than the NIP determined for the domestic industry.

Price Suppression/Depression

49. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015 - September 2016 (POI)
Cost to make & sell	Rs. per doz.	***	***	***	***
	Indexed	100	109	118	119
Domestic Selling Price	Rs. per doz.	***	***	***	***
	Indexed	100	109	114	121
Landed Value	Rs. per doz.	***	***	***	***

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015 - September 2016 (POI)
	Indexed	100	105	120	134

50. It is noted that the cost to make and sell the like articles have increased and the selling price of the same has increased proportionately. The landed price of imports have also increased.
51. The domestic industry contended that the data shows that the Authority's observations that there is no suppression or depression is baseless. It is however seen that whereas landed prices of imports have increased on an average by 33%, domestic industry increased its prices by 21% and the cost of sales increased by 19%. Thus, the domestic industry was able to increase its price more than the cost of sales and simultaneously, it did not increase its prices to the extent of increase in landed price of imports. Thus, the imports were not suppressing/depressing the domestic industry prices.

Economic parameters of the domestic industry

52. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

53. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	Annualized
Total Installed Capacity	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	114	115	114
Parkson Graphics	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	109	109	114
Parkson Cartamundi	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	100
TM printers	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	130	134	129
Total Production	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	104	102	110
Capacity Utilization	%	58	53	51	56

54. The assessment of the installed capacity and capacity utilization of the product under consideration for the three petitioners show that these parameters have remained more or less same throughout the injury period.
55. The domestic industry has raised concerns about range of capacity utilization being given instead of actual percentage. The same has been incorporated above.
56. It has been observed that the petitioners have enhanced capacities despite their admitted claims of underutilized capacities. Despite increase in capacity by 14% and existing unutilized capacities before capacity expansion, the capacity utilization of the domestic industry decreased only marginally in POI when compared to base year.

ii. **Profitability**

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015 - September 2016 (POI)	Annualized
Parkson Graphics	Rs. in Lakhs	***	***	***	***	***
	Indexed	(100)	48	(379)	(1318)	879
Parkson Cartamundi	Rs. in Lakhs	***	***	***	***	***
	Indexed	(100)	(135)	(182)	(65)	(44)
TM Printers	Rs. in Lakhs	***	***	***	***	***
	Indexed	100	155	79	98	66
Total Profits	Rs.	***	***	***	***	***
	Indexed	(100)	(46)	(556)	136	136
Profit per dozen	INR	***	***	***	***	***
	Indexed	(100)	(43)	(513)	120	120

57. The Authority notes the following from the above table:

- a. The domestic industry's profitability has not been affected. The domestic industry has been suffering losses during 2013-14 but made significant profits thereafter during the POI. On examination, this pattern of profit could not be directly correlated with import prices. Therefore, the causal link of dumped imports with profitability is not clearly established.

iii. **Return on capital employed**

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015 - September 2016 (POI) Annualised
PBIT	Rs. lakhs	***	***	***	***
	Indexed	100	170	56	177
Capital Employed	Rs. lakhs	***	***	***	***
	Indexed	100	138	139	147

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015 - September 2016 (POI) Annualised
PBIT	Rs. lakhs	***	***	***	***
	Indexed	100	170	56	177
Capital Employed	Rs. lakhs	***	***	***	***
	Indexed	100	138	139	147
ROCE	%	***	***	***	***
	Range	5-15%	5-15%	0-10%	5-15%

58. The Authority notes that the domestic industry has been able to earn an adequate return on capital employed throughout the injury investigation period.

59. Further, both profit before interest and capital employed has been significantly high during the period of investigation.

iv. Market Share

60. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualized)
Total demand	Dozen	***	***	***	***
	Indexed	100	113	114	122
Market Share of					
- Petitioners	%	***	***	***	***
	Range	40-50	40-50	40-50	40-50
- Supporters	%	***	***	***	***
	Range	20-30	20-30	20-30	20-30
- Other Producers	%	***	***	***	***
	Range	0-10	0-10	0-10	0-10
Share of imports from China PR	%	***	***	***	***
	Range	20-30	20-30	20-30	20-30
Share of imports from other countries	%	***	***	***	***
	Range	0-10	0-10	0-10	0-10

61. The Authority observes that the market share of the Domestic Industry has decreased minimally even though demand for the subject goods has been rising in India.

62. The sales of the PUC of the domestic industry has not increased commensurate with the increase in demand.

63. It is noted that market share of domestic industry declined marginally by 3% whereas market share of supporters increased by 1%. Decline of market share of domestic industry is not significant. Further, the argument that huge imports have killed market share of domestic industry is not tenable considering supporters have increased market share.

v. Inventories

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015 - September 2016 (POI)
Production	Dozen	7,582,777	7,851,7774	7,708,030	8,370,569
	Indexed	100	104	102	110
Average Inventory	Dozen	***	***	***	***
Inventory as no.of days of production		10	15	19	17
Average Inventory	Indexed	100	151	182	179

64. The Authority notes that the Domestic Industry has accumulated inventories. The levels of inventories have increased throughout the injury period. However, the average no. of days for which the domestic industry was holding production in stock was calculated. It is found that the holding number of days production in stock is not very high.

vi. Productivity of the domestic industry

65. The Authority notes that employment level of the domestic industry does not show any adverse effect during the POI. Further, productivity per employee has remained healthy as observed from the table below.

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	POI
No. of Employees	***	***	***	***
Indexed	100	115	137	114
Productivity per employee	***	***	***	***
Indexed	100	90	74	145

Ability to raise capital investments

66. The Authority notes that given the rising demand of the product in the country, the domestic industry has made significant investments in plant and machinery. Further, the possibility of injury to the domestic industry caused by the increased investments in plant and machinery instead of dumped imports cannot be ruled out given the best available information on record.

Level of dumping & dumping margin

67. It is noted that imports from the subject country are entering into the country at dumped prices and that the margins of dumping are significant.

Factors Affecting Domestic Prices

68. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc., market share of the domestic industry, supporting producers and imports, change in cost of production and selling price of the domestic

industry, level of price undercutting, dumping margin and injury margin does not clearly establish that the landed value of imported goods from the subject country is caused significant depressing or suppressing effects on the prices in the Indian market. While imports increased over the injury period, sales of petitioners and supporters also increased and the domestic industry was able to increase its prices more than increase in cost of production.

G. OVERALL ANALYSIS ON INJURY

69. Having regard to the information on record and after examination of the performance of the Domestic Industry, the Authority notes that the dumped imports of the subject goods from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption of the subject goods in India. Import prices of the product are lower than the non-injurious price of the subject goods. The demand for the product has increased significantly and imports from China PR has a major share in the increase in demand. However, the Domestic Industry's profitability and return on capital have increased substantially during the period of investigation. Inventories increased but number of employees has also increased along with their productivity.

H. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

70. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry has been done as follows:

Imports from third country

71. The imports from country other than subject country are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. Moreover, the price at which goods are coming from other country is much higher than the price at which goods are coming from subject country.

Contraction in demand

72. The demand for the subject goods has shown an increasing trend. Accordingly, fall in demand cannot be the reason for injury to the domestic industry. In fact, the domestic industry has not been able to increase its sale and market share commensurate to increase in demand.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

73. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

Developments in technology

74. The technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor of causing injury to the domestic injury.

Changes in pattern of consumption

75. The domestic industry is producing the type of goods that have been imported into India. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

Export performance

76. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export performance of the domestic industry. In fact, exports by the domestic industry have not materially declined.

Performance of the domestic industry with respect to other products

77. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

Productivity of the domestic industry

78. The Authority notes that the major economic parameters of injury assessed in preceding analysis have shown substantial improvement of the performance of the domestic industry in the period of investigation.

Indian industry's interest & other issues

79. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

Magnitude of Injury Margin

80. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry and compared with the landed values of the subject imports from the subject country to determine the injury margin. The injury margins have been determined as follows:

Injury Margin

Particulars	Unit	Based on DGCIS Import Data
Landed value	Rs per Doz.	***
NIP	Rs per Doz.	***
Injury Margin	Rs. per Doz.	***
	USD per Doz.	***
	%	***
	% range	360-370

81. The level of dumping margins and injury margins as determined are significant.

I. POST DISCLOSURE STATEMENT

82. The issues raised at post disclosure stage have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties have been summarized and again addressed as below. Further, issues have been addressed at respective paras in the present Final Finding:

Submissions made by the Domestic Industry

83. The comments submitted by domestic industry are summarized as below:

- i. The product being imported and manufactured by the petitioners are comparable and are like articles.
- ii. Making PCN in the present case would not have served any objective because of no cooperation of the exporters in the present case it was not possible for the authority to compare data at PCN classification basis.
- iii. Import data does not provide for any basis for segregation.
- iv. The weighted average determination of dumping margin, price undercutting and injury margin, as suggested by the petitioners is the best course of action in the given situation.
- v. The Authority has rightly examined the standing of the domestic industry. In case of unorganized and fragmented sector the Authority has always examined the base of domestic industry on the basis of credible and reliable information.
- vi. The dumping margin in the disclosure statement is significant. If the Authority undergoes a change or revival the examination, the domestic industry should be given an opportunity to address it properly.

- vii. The Authority failed to examine that the demand increased by 22% but sales of the domestic industry as increased only by 13% in fact sales of the other producers, apart from the supporters, have declined by 17%.
- viii. The Authority needs to write that imports have increased in absolute as well as in relation to production and consumption showing a clear intent to take over the domestic market at the risk of local manufacturers and supply.
- ix. Authority's observation that there's no suppression or depression is baseless.
- x. The disclosure statement has given range of capacity utilization which is not a usual practice. In actual figure the capacity utilization has declined in the Period of investigation and 40-50% capacity remains unutilized.
- xi. 25% of the demand has been taken over by Chinese imports. Petitioner is suffering volume injury due to keeping the price at remunerative level.
- xii. The authority has wrongly held that domestic industry earned significant profit in Period of investigation. So there cannot be a causal link between profitability and dumped imports. The domestic industry earned profit of Rs. 1-2 per dozen where the total cost of the product is 175-180 per dozen.
- xiii. The Authority needs to examine actual as well as potential situations of economic parameters.
- xiv. Rs. 1-2 per dozen profits cannot tarnish the causal link.
- xv. Domestic industry fails to understand how the Authority has called 7-10% ROCE as "adequate". Why the Authority is not agreeing to its consistent practice of agreeing to 22% ROCE.
- xvi. Domestic industry is not capital intensive one and therefore even the standard 22% ROCE is not sufficient for their survival leave alone 7-10% earned by them.
- xvii. Inventories increased due to excessive dumping
- xviii. The Authority has given range of market share against the usual general practice. The market share of the domestic industry has declined despite increase in demand.

Submissions made by the Exporters/producers and other interested parties

84. The comments submitted by other interested parties are as below:
- i. Different kinds of playing cards, in terms of cost and price, cannot be treated as one product. The interested parties are not supposed to file information regarding PCN.
 - ii. The petitioners should have brought all the information before the authority while filing the petition. The approach followed by the petitioners was mala fide in not providing information and now shifting the blame onto the interested parties for not suggesting relevant criteria.
 - iii. Information on PCN always first comes in from the petitioners, as it is the petitioners who is in possession of relevant information not only with regard to imports but also with regard to their own data.
 - iv. The fact that the description contained in the import data is entirely irrelevant. The petitioners could adopt any of the approach suggested to suggest PCN and thereafter determine dumping margin and injury margin.
 - v. Is it the case of petitioners that they have been irrationally fixing price of different product types and the difference in prices charged by them bear no standard parameter/criteria and the petitioners have been taking the consumers for a ride?
 - vi. At present, the petitioners have not even suggested a PCN methodology and instead have taken an approach that there are no standard parameter / criteria available to classify the product in to different categorizes / grades. This is clearly untenable.
 - vii. The present investigations are required to be terminated, instead of resorting to Rule 6(8). If, the petitioner themselves agree that there is no criteria, it follow that the authority cannot make an appropriate determination in the present case.

- viii. The interested parties had written to the Authority, soon after initiation, where the price list of the petitioners was enclosed and the price range of the petitioners were analyzed. The Authority had placed those letters in public file for inspection of the petitioners.
- ix. On careful examination of the imports data it can be seen that in various line item it is mentioned in the description of product “playing cards made of paper”, “100% plastic playing cards”, “low quality paper playing cards”. Sample of the import listing (T/T) is enclosed with the submission for your kind reference. The petitioners made no efforts in analyzing the import data for segregating it in various types.
- x. Based on the accuracy and adequacy of the information the present investigations need to be terminated.
- xi. The imported products are made of low quality paper and recycled paper. It targets different segment of consumers whereas the product manufactured by the petitioners are high quality paper or plastic playing cards. Significant proportion of the product manufactured by petitioners is of plastic.
- xii. It can be prima facie seen that the petition is filed by Mumbai based manufacturers. Even the members of Indian Playing Cards Associations are Mumbai based. The petitioners have made no efforts to include Delhi based manufacturers in the scope of domestic industry.
- xiii. With such huge dumping margin, injury margin and price undercutting, the imports have not accelerated at an alarming rate.
- xiv. Given this kind of price difference between the domestic and imported product, the petitioners are unable to explain how the petitioners were able to increase their production and sales.
- xv. Despite more than 300% price difference between domestic and imported product, it is amazing that the production & domestic sales of the petitioners improved and the petitioners have contended that they have been adversely affected by the dumped imports.
- xvi. This clearly shows that like articles are not being compared. Imports are of different variety/category of playing cards as compared to the domestic. The two are being sold in two different market segments. The two are not competing with each other.
- xvii. The interested parties had analyzed the alleged injury being suffered by the domestic industry. The interested parties had compared all the injury parameters of the domestic industry from all the years to the Period of investigation.
- xviii. Apart of subject imports, imports from other countries, sales of petitioners and other producers also have increased significantly.
- xix. The demand figures only include sales of Mumbai based producers and does not include sales of Delhi based producers and producers of other parts of India. If the sales of other Indian producers are included, it would be seen that petitioners have lost their market share to other Indian producers.
- xx. Production of each of the petitioner companies have increased. The capacity utilization of the domestic industry has remained constant throughout the injury period.
- xxi. The production has increased over the injury period. Further, the capacity utilization change is so insignificant that the same falls within the same range over the injury period, thus leading to no change in indexed capacity utilization.
- xxii. Capacity was expanded by the petitioner despite huge unutilized capacities.
- xxiii. The price undercutting and price underselling determined is not based on fair comparison and therefore cannot form basis for imposition of duties.
- xxiv. The Authority has rightly held that profitability has not been affected, the petitioners were suffering losses during 2013-14 but made significant profits thereafter during the Period of investigation.
- xxv. Sales, production, capacity and capacity utilisation, all of these trends have shown improvement throughout the injury period. The sales of not only the petitioners but the supporters and other producers have also increased.

- xxvi. It can be seen that ROCE, ROI and profitability of the domestic industry has shown tremendous growth.
- xxvii. The change in the market share is so insignificant that the same have remained in same range over the injury period. This clearly shows that none of the interested parties have suffered on account of market share.
- xxviii. Inventories with the petitioners have increased. The same is however due to rising production and wide range of product that any supplier must offer in the market.
- xxix. There is huge demand-supply gap.
- xxx. The Authority is requested to examine other known factors such as inter-se competition amongst domestic producers. The price list of different manufacturers shows that (a) these manufacturers must be fiercely competing with each other, (b) price difference between the domestic and imported product is so significant that there can be no competition between the domestic and imported product, (c) the imported product competes with the product produced and sold by low-end producers such as Delhi based producers.

Examination by Authority

- 85. Some of the issues raised at post disclosure stage have been examined in above relevant paragraphs.
- 86. The petitioner contended that the Authority needs to examine actual as well as potential situations relating to economic parameters. It is, however, noted that petitioner has submitted no claim with regard to potential situations relating to injury to the domestic industry and economic parameters. When, the petitioner has not even claimed injury on account of potential effects of dumped imports on the domestic industry, the Authority could not examine potential effects of the dumped imports on the domestic industry.

J. CONCLUSION

- 87. The conclusion is summarized below:
 - a. The Authority notes that the volume of imports of the product under consideration have increased over the injury period in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The dumping margin, price undercutting and injury margin are positive and significantly high. However, despite such high degree of dumping margin, price undercutting and injury margin, the domestic industry has been able to enhance its capacity and its production. Further, sales improved over the injury period.
 - b. While market share of domestic industry declined, it is noted that the market share of supporting producers increased over the injury period.
 - c. Even when the level of inventories increased, the absolute level of inventories with the domestic industry were not so significant considering the rate of production and wide range of playing cards produced and sold by the domestic industry.
 - d. Despite such significant dumping margin and price undercutting, the imports did not suppress or depress the domestic industry prices and the domestic industry was able to improve its profitability, cash profits and return on investment.
 - e. Dumped imports of the product were not a factor affecting the domestic prices,
considering that the domestic industry did not face suppressing or depressing effect as a result of huge price undercutting.
 - f. The consequent impact of dumped imports on the domestic industry performance is therefore absent. It could not be conclusively established that the domestic industry suffered injury as a result of dumped imports.

K. RECOMMENDATION

88. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal links. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal links in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules. The authority notes that there is no causal link between the dumped imports material injury to the domestic industry due to reasons give above. Therefore, in terms of Rule 14 (b), (e) and Rule 17(1)(iii) read with Rule 11(2) and para v of Annexure II of the Anti-Dumping Rules, the Designated Authority decides to terminate the present investigation which was initiated vide Notification No. NO. 14/43/2016 – DGAD dated 30th March, 2017

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority